साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 6 अंक 4 प्रति सोमवार इंदौर, 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2012 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

राष्ट्रगीत नहीं गुलामी का गीत

गीत गुलामी का गायेंगे, गुलामी फिर लायेंगे

कांग्रेसी गिरोह राष्ट्र को बेच व गिरवी रख, हमें गुलाम बनाने कटिबद्ध

हमारे राष्ट्र का, राष्ट्रगीत जन,गण,मन अधिनायक जय हैं, भारत भाग्य विधाता, अर्थात जन और उनके चुने हुये गण मन से उस अधिनायक, जिनके हम 65 वर्षों पूर्व अधीन थे, जो हमारे नायक थे कि जय है, जो हमारे भाग्य विधाता थे और 65 वर्षों की आजादी के बाद भी आज भी हैं और कल भी हम जब तक ये गीत गाते और राष्ट्र के 30 करोड़ बच्चों से स्कूल में गवाते रहेंगे, हम स्वयं उन अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे।

इस धरती पर जो सब कुछ दिख रहा, बांध, बिजली, सड़कें, लोकसभा, बहुमंजिला इमारतें आखिर किस का परिणाम हैं। ये सब जो दुनिया में बसा हुआ दिख रहा है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का परिणाम है, यदि आप गुलामी का गीत गायेंगे, अर्थात गुलामी की इच्छा है, तो आप पुनः गुलामी बुलायेंगे, जो धीरे-धीरे बहुराष्ट्रीय कं. के व्यापार के बहाने पुनः आ रही है।

आखिर इस देश की सोना उगलने वाली धरती से धन इकट्ठा करके विदेशों में जमा करवाकर उन्हें समृद्ध किया जा रहा है, जबकि इस राष्ट्र की और राष्ट्र की जनता की समृद्धि के लिये क्यों विश्व बैंक एशियन विकास बैंक से उधार लिया जा रहा है। और वह धन भी भ्रष्टाचार में पीकर उनके हिसाब से नाच कर हम पुनः विदेशी आकाओं को अपने राष्ट्र में स्वागत करने पर तुले हैं।

सीधा सा उत्तर है, जिस राष्ट्र के 30 करोड़ बच्चे और युवा यदि राष्ट्रगीत ही गुलामी का गाकर जन,गण,मन अधिनायक करेंगे और उन आक्रांताओं को अपना भाग्य विधाता कहकर जय जय कार करेंगे, जिन्होंने 300 वर्ष इस राष्ट्र को गुलाम बनाकर रखा, तो क्या होगा, न केवल इस राष्ट्र के लोक वरन् पंजाब, सिंध (जो अब भारत में नहीं है) गुजरात, मराठा, द्रविण, उत्कल (उड़ीसा), बंग (बंगाली), विंध्य, हिमाचल अर्थात हिमालय, उच्छल, जलधि तरंग, इन सबसे भी यदि गुलामों की तरह शीश नवायेंगे, उनकी चरण वंदना करवायेंगे जैसी इच्छायें रखेंगे, करेंगे, करम भी वैसे ही करेंगे और फल भी वैसे ही मिलेगा और निवेश के बहाने गुलामी के फल अब पकने लगे हैं। परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

अर्थात निवेश के बहाने हम जिन बहुराष्ट्रीय कं. यथा इंडियन टोबेको कं. जो ब्रिटिश टोबेको कं. की सहयोगी कं. है, भारत में सिगरेट से लेकर खाद्य तेलों, खाद्य पदार्थों से लेकर अब वृहद स्तर पर हर छोटे जिले के कोने पर आईटीसी हरियाली के नाम किसानों की एक तरफ फसल ओने-पौने में खरीदकर उसे सिगरेट से लेकर घरेलु और कृषि कार्य का समी सामान ट्रेक्टर तक न केवल बेच रही है वरन उत्तर प्रदेश और काश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती कर उत्पादन कर रही है, जिसने लाखों किसानों को बेरोजगार कर दिया है। अब जब फुटकर व्यवसाय में 100% निवेश को मंजूरी दी जा रही है। उनके पक्ष में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाकर पूरी तैयारी है। 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया जाये, देश के ही 10 % ऐसी बहुराष्ट्रीय कं. में नौकरी करेंगे और मनचाही कीमतों पर जब उनके सारे छोटे प्रतियोगी समाप्त हो जायेंगे, माल बेचकर अपने देश में फिर धन भेजेंगे, जब पूरे सभी राजनीतिक दलों के नेता उनके टुकड़ों पर पलने लगेंगे तो फिर उनके भी पिछाड़ू चार लातें मारकर पूर्व की ही तरह राष्ट्र की सत्ता पर कब्जा जमा लेंगे, पूर्व में ईस्ट इंडिया कं. व्यापार करने ही आई थी। (शेष पृष्ठ 2 पर)

ओबामा-भारत बाप की जागीर नहीं है

भारत में फुटकर व्यवसाय में निवेश की वकालत

अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था चौपट करने में इन्हीं बहुराष्ट्रीय कं. का हाथ है, भारत को चौपट करने पर क्यों तुले हो, बहुराष्ट्रीय कं. की गिद्ध निगाहें भारत पर

अमेरिका में आगामी अक्टू-नवम्बर 12 में राष्ट्रपति का चुनाव है, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इन बहुराष्ट्रीय कं. से भारी करोड़ों डालर में चुनावी चंदा हजम किया है, बदले में उनका अपने चुनाव प्रचार करने के साथ ही व्यवसाय संवर्धन का कार्य भी कर रहा है। अब जबकि अमेरिका के साथ ही पूरा यूरोप का उपभोक्ता बाजार मंदी की मार से पीड़ित है, पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कं. की गिद्ध निगाहें भारत के सदैव हरा-भरा रहने वाले उपभोक्ता बाजार पर लगी है। और भारत में पैर जमाने के लिये आने से पूर्व ही हजारों करोड़ रु. की रिश्वत बांटकर अपने पक्ष में माहौल बनाने सत्ताधीश सांसदों को खरीदकर पहले कानून बनवाये गये, जिसमें सबसे प्रमुख था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06, जो कानून प्रभावी था, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 को समाप्त करवाया गया, ताकि ये जनता को कुछ भी खिलाये-पिलायें जैसा कि शीतल पेयों में इंडोसलफान जैसे घातक मिला कर राष्ट्र की जनता को वर्षों से पिलाकर देश की बाल और युवा पीढ़ी को न केवल नपुंसक वरन उन्हें वृद्धावस्था की बीमारियां यथा हृदयाघात, यकृत खराब होना, हार्मोन्स की कमी, स्त्रियों की अनेकों बीमारियां जो पहले 50-60 की उम्र में होती थी, इन्हीं विषों के प्रभाव से 15-20 वर्ष की उम्र में भी होने लगी है। परन्तु अब ऐसे किसी भी घातक विषयुक्त खाद्य पदार्थों में सजा का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, अब केवल अर्थदंड होगा। भारत में ऐसी बहुराष्ट्रीय कं. जैसे वाल मार्ट, मेकडोनाल्ड से लेकर अनेकों बहुराष्ट्रीय कं. भारत में फुटकर व्यवसाय में सदा हरियाली वाले बाजार में पैर पसारने के इंतजार में पिछले कई वर्षों से बैठी हैं।

भारत में फुटकर बाजार में निवेश के लिये जहां कांग्रेस उतावली बैठी है, वहीं उसी कांग्रेस के साथ यूपीए के घटक दलों में शामिल दूसरे गिरोह के सदस्यों जिसमें खास तौर पर लालची सौदेबाज बंगालिन ममता बनर्जी भी इसका विरोध कर रही है, जिसे मनाने के लिये बराक ओबामा ने अपनी चेलीं हिलेरी क्लिंटन को भेजा था, जो कि सेक्स वर्करों के बच्चों की सहायता के नाम कोलकता में ममता से ही मिलने गई थी, उसका मूल उद्देश्य भी यही था कि वो फुटकर व्यवसाय में बहुराष्ट्रीय कं. और विदेशी निवेश का विरोध करना बंद कर दें।

बंगालिन मुख्यमंत्री के चाल चरित्र से राष्ट्र को और विश्व को ये तो ज्ञात हो ही चुका है कि पिछले 15 वर्षों के इतिहास में उससे अपनी शर्तें मनवाने के लिये उसे मोटा पैकेज देकर ही खरीदा जा सकता है। जैसा कि वह अटल सरकार के बाद मनमोहन की सरकार में भी करती आ रही है। हाल में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी सौदेबाजी के बाद ही मुखर्जी के पक्ष में ही मतदान किया, ये सब अब मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जनता देखती है। अर्थात एफडीआई के पैर जमाने में आज नहीं तो कल बनर्जी को मोटा पैकेज लेकर हां कर देगी इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं बशर्ते की कांग्रेस सरकार पूरी ताकत से एफडीआई के पक्ष में माहौल बनाये। कांग्रेस और उसके संप्रग सहयोगी सभी भुखेरे गिद्धों की फौज है, वो तो अमेरिकी इशारे पर नाच कर ही उन्होंने 2005 में सत्ता संभालते ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06 सब को पैसा बांटकर संसद में पास करवा लिया था जो पूर्णतः इस राष्ट्र के करोड़ों लोगों से रोजगार छीनकर सब बहुराष्ट्रीय कं. के हाथों में जनता को नोंचने के लिए छोड़ देगा। वो बहुराष्ट्रीय कं. यहां से कागज के टुकड़ों की अपेक्षा सोना-चांदी और बहुमूल्य धातुएं ले जायेंगी बदले में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों की तरह भारत को और उसकी जनता को कंगाल बना देंगी, चूंकि ओबामा ने उन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा चंदा चुनाव के लिये वसूला है। (शेष पृष्ठ 7 पर)

मनरेगा विदेशी षड्यंत्रकारी बहुराष्ट्रीय कं. को धन से प्रयोजित

देशी किसानों को बर्बाद कर कृषि भूमि हथियाने का षड्यंत्र

- आईटीसी ने 2010 तक 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हथिया ली थी
- कार्पोरेट फार्मिंग के लिये 2 लाख से ज्यादा किसान बेरोजगार किये

अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय ही ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अधिकतम 70-80 वर्षों में देश को फिर गुलाम बनाया जा सके, इसलिये उसने 1885 में स्वयं ही कांग्रेस की स्थापना कर अपने विरुद्ध भड़ास निकालने अपने को महान सिद्ध करने अपने जाने के बाद भी अपनी शान-शौकत और महानता और पुनः अपनी अगुवाई करने के कार्यों को संपन्न किया जाता रहे और फिर आसानी से 50-100 वर्षों में गुलाम बना सकें। वर्तमान में अंग्रेजों की ये रखैलों की औलादें बारकुबी संपन्न कर रही है। जिस मंतव्य से उन्होंने अपने गुलाम देश में कांग्रेस की स्थापना की थी, कांग्रेसी सरकारें उनके नक्शे कदम पर चलकर इस राष्ट्र को पुनः गुलामी की तरफ ले जा रही हैं। इस कार्य पर निगरानी रखने उन्होंने स्व. राजीव गांधी की शादी इटालियन सोनिया जो केंब्रिज के रेस्टोरेंट कम होटल में काम करती थी, दिस. 1965 में मुलाकात करवाकर 1966 को स्व. राजीव गांधी के संग भारत भेज दिया, अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में 1969 में स्व. इंदिरा गांधी ने शादी के लिये हां की, 1966 से लेकर वर्तमान तक में ये विदेशी एजेन्ट सोनिया सत्ता के शीर्ष में बैठकर अपने आकाओं के इशारों पर नाचकर इस देश में षड्यंत्रों की रचना से लेकर कानूनों को बनवाने और देश की जनता को गुलाम समझकर विदेशीयों की रीति-नीति को राष्ट्र पर थोपने में लगी है। जब तक इंदिरा गांधी सत्ता में जीवित थी तब तक ये ज्यादा खेल नहीं खेल पाई, फिर भी षड्यंत्रों से कभी बाज भी नहीं आई, स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्व. राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के साथ ही उसके षड्यंत्रों की हर कारगुजारी सफल होने लगी, पहले लिट्टे को प्रशिक्षण, हथियार, वित्तीय सहायता दी गई, फिर राजीव की हत्या, फिर उसी लिट्टे पर भारतीय सेना द्वारा उस लिट्टे को न केवल खत्म करवाया वरन् लाखों तमिलों की श्रीलंका में हत्या में भी अहम रोल किया, एक तरफ श्रीलंका में 1988 से लेकर संहार करते रहे तो दूसरी तरफ मोटा धन डकारने, हथियार खरीदने का बहाना ढूंढने, काश्मीर को आतंकवादियों की और वर्तमान में भी आतंकवादियों को पालकर मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिये आतंकवादियों को काश्मीर से कन्याकुमारी तक मुर्ग मुस्लम, चिकन अफगानी बिरयानी जनता के धन से परोसते रहे। (शेष पृष्ठ 7 पर)

सत्ता-सत्ताधीशों के बाप की जागीर नहीं फिर भी

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह सर्वोच्च न्याया. से भी बड़ा

स. न्या. का फैसला मानने से साफ इंकार, हम जो चाहेंगे करेंगे

म.प्र. में भाजपा की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा चंदा और वोट सवर्णों ने दिये। जिसके दम पर ये सत्ताधीश वर्तमान में सत्ता का उपयोग कर उन्हीं सवर्णों को ये जालसाज, धूर्त, हरामखोरों की फौज न केवल कदम-कदम पर हड़का रही है, उनके व्यापार धंधों से लेकर नौकरियां करने के अधिकार से भी वंचित कर रही हैं। लोकतंत्र में भी सत्ता पाते ही हर सत्ताधीश सत्ता के मद में चूर हो, अपनी औकात भूल जाता है। जिसके दम पर वह सत्ता में आता है उसी को हड़काता है, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके ऊपर अनाप-शनाप कर लादता है। उन्हें डराता-धमकाता है। उनकी रोजी-रोटी छीनता है। कानून लादता है। उनकी संपत्तियां छीनता है। जमीनें छीनता हैं और अपनी कमाई के लिये मोटा धन देने वालों को सौंपने के लिये इंवेस्टर्स मीट करवाता है। गरीबों और कमजोर लोगों की बस्तियां छीन ली जाती हैं।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

कुंठा, ज्वालामुखी से ज्यादा घातक

पृथ्वी पर प्रकृति ने सभी जीवों का मस्तिष्क दिया है, जिसके आधार पर उसकी प्रकृति और कार्य भी निर्धारित किये गये हैं। पृथ्वी पर मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, पूरे विश्व में वर्तमान में जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, जो प्रकृति के इतर की श्रेणी में आते हैं। यथा लाखों कि.मी. की सड़कें, बहुमंजिला इमारतें, शिक्षा, शास्त्र ग्रंथ आदि असंख्य मानव निर्मित दुनिया, मनुष्य की इच्छाशक्ति का ही परिणाम है, इससे ही मानव की इच्छाशक्ति और उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसके विपरीत जिसे हम तत्काल में शुभ समझते हैं। वह दीर्घकाल में अशुभ हो सकता है और जिसे तत्काल में अशुभ समझते हैं। वह दीर्घकाल में शुभ हो सकता है।

ये मनुष्य की इच्छाशक्ति का ही परिणाम था कि उसने नदियों पर बांध बनाकर पानी रोक दिया, उसमें से नहरें बनारकर वर्ष भर पानी का अपनी तरह से उपयोग किया। पक्षियों को उड़ता देख उसने भी विमान बना लिये और आकाश में स्वयं के पंख न होने पर भी उसने प्रकृति प्रदत्त धातुओं से अपना साकार किये, जब मानव की इच्छाशक्ति के अनुकूल कार्य संपन्न नहीं होते, उसके कार्यों में उसका ही सहयात्री उस पर अपन इच्छा शक्ति से उसे बाधित करता है, या अपने धन, बल, स्वार्थ से उस दबाव बनाता है, या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य संपन्न होता हैं, तो जो मस्तिष्क में आक्रोश उत्पन्न होता है, यदि स्खलित नहीं होता जो जनम होता है कुंठा का, यह कुंठा ही थी, जिसने भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम रखा, यह कुंठा कितनी घातक होती है इसका अंदाज लगा पाना तो मुश्किल है, पर यह कुंठा ही होती है, जो ज्वालामुखी से ज्यादा घातक है।

इतिहास बताता है कि भारत में हजारों की गुलामी झेली है, अलेक्जेंडर सेल्युकस 22-25 वर्ष के लौंडों ने आकर देश को पूरा जीत लिया, क्योंकि राजाओं को जनता के शोषण और अपने पोषण अय्याशी से फुर्सत नहीं मिलती, जनता कुंठित हो जाती थी, बाद में कोई भी आक्रांता आसानी से करा था और आसानी से कब्जा कर लेता था। कम्युनिज्म में जब सबको रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधा मिल रही थी, जो कि पूंजीवाद के घोर शोषण के परिणाम स्वरूप निर्मित की गई थी, इसके विपरीत आखिर उस कम्युनिज्म में घोर शोषण, न बोलने की आजादी, न लिखने की आजादी आखिर वह कुंठा फटी, और उस कम्युनिज्म का भी आखिर 1986 में अंत हो गया और सोवियत रुस खंड-खंड होकर 26 टुकड़ों में बंट गया, यह कुंठा का ही परिणाम था जो सोवियत रुस खंड-खंड बिखर गया।

यही हाल मेरे राष्ट्र का होने वाला है। शायद नास्त्रेदम की भविष्यवाणी पूरी होने का वक्त ला रही हैं, वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकारें, जो जनता का घोर शोषण अपने नोट और वोट बैंक के लिये कर रही हैं। एक तरफ जिन सवर्णों पर सबसे ज्यादा कर थोपे जाते हैं। काम लिया जाता हैं, वसूलियां अपने चुनावों के लिये चंदा लेने से लेकर रिश्वत लेने तक में उन्हीं सवर्णों को जो 30-40% सरकारी सेवाओं में हैं भी करते हैं। उनको संविधान की समानता के विपरीत रोजगार व्यवसाय और पदोन्नतियों में 25, 30-35 वर्ष तक पदोन्नतियां न देकर खुले में उनके ही कनिष्ठ उनका न केवल घोर अपमान कर प्रताड़ित भी करते हैं। अगर वो सच भी बोलते हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति अधि. के अंतर्गत धमकाया जाता है कि ज्यादा सच बोलोगे तो अभी तुम्हारी पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा दी जायेगी, यह देश की रोजमर्रा की जिंदगी में बरसों से चल रहा है, यहां तक कि प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी आर.एस. जुलानिया की भी इस अधि. के अंतर्गत एफआईआर करवा दी गई। भाजपा जिसका जन्म 1980 में हुआ, तब से लेकर अभी तक इन्हीं भाजपाइयों की जो अब सत्ता में हैं। उन्हीं सवर्णों ने इन्हें जीवित रखने में नोट और वोट दिये, सत्ता भी आसीन कराया कल तक सायकलों, स्कूटरों पर घूमने वाले अब हजारों करोड़ के मालिक इनके दम पर ही हैं। अब वो ही मुख्यमंत्री, मंत्री, संत्री, खुले में अपमान करते हुए कहते हैं कि नहीं, पदोन्नतियों में आरक्षण दिया जायेगा, जब ये सारे सकों पर नोट और वोट की भीख मांगते केवल सवर्णों के घर ही जाते थे, तब इन जालसाजों को मालूम था कि इन्हें हरिजन आदिवासियों और मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, अब वही आर.एस.एस. के सुदर्शन मुस्लिमों को वोट दिलवाने के लिये इस 20 अगस्त 12 की ईद पर मुस्लिमों के साथ नमाज अदा करने के भोपाल में घूम रहे थे, किसी भी धर्म को जानना, मानना बहुत अच्छा है, परन्तु जहां स्वार्थ और लाभ प्राप्ति की इच्छा जाग्रत हो, किसी धर्मावलंबी को यह गवारा नहीं और इस स्वार्थपूर्ण मानसिकता कोई कुछ बोले न बोले, पर सब समझदार हैं, सबके मस्तिष्क में घृणा ही पैदा करते हैं इसे सभी जालसाजी पूर्ण कृत्य। सत्ताधीश चाहे वो केन्द्र की कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गिरोह हो या भाजपा का राजग यदि अपने नोट और वोट बैंक के लिये संविधान की समानता की भावना को कुचलकर वोट धर्म, और लूट धर्म का पालन कर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की घोर शोषणकारी नीति का पालन करने से जो राष्ट की 125 करोड़ जनता के मस्तिष्क में कुंठा और आक्रोश पनपेगा, ऐसा न हो कि जनता मन ही मन ये राष्ट्र को ऐसी शोषणकारी सत्ता को नष्ट होने की कामना करने लगे, परिणाम स्वरूप चारों तरफ शत्रुओं से घिरे राष्ट्र पर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ से आक्रमण हो जाये, जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु 50 वर्षों से लगातार हरकतें कर ही रहे हैं। कुंठा और आक्रोश का ही परिणाम थी अन्ना और रामदेव के आंदोलनों की राष्ट्रव्यापी भीड़, चूंकि आंदोलन का उद्देश्य ही सही नहीं था, इसलिए उसे बिखरना ही था, पर भी से सत्ताधीशों को अपनी शोषणकारी नीतियों और कुंठा का अंदाज लगा लेना चाहिए था । इस बात से खुश सत्ताधीश कि उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक आंदोलन कुचल दिया, जबकि ये कुंठा यदि जनता के मस्तिष्क में संप्रहित हो रही है तो विस्फोटक रूप लेगी।

लोकतंत्र में चाहिये लोक और तंत्र दोनों समृद्ध और मजबूत हों

सत्ताधीशों का यथार्थ - नोट और वोट

लोक और तंत्र दोनों जायें भाड़ में, कैसा लोक और कैसा तंत्र

भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंग यथार्थ में सरदार भ्रष्टाचार सिंग, घोटाला सिंग, बहुराष्ट्रीय कं. के भारतीय एजेन्ट सिंग बनकर उभरे हैं। जिसने अपने प्रधानमंत्री काल में केवल नोट और वोट की राजनीति कर रहा है। उसे राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों के भविष्य की सुख-समृद्धि की अपेक्षा अपनी और अपनी आका यूरोपियन एजेन्ट सोनिया गांधी के भले से मतलब है।

2जी-3जी में पौने तीन लाख करोड़, कोयला घोटाला साढ़े 10 लाख करोड़ तो भारत के महा अंकेक्षक और नियंत्रक ने पकड़ लिये, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग में 7000 कि.मी. सड़कें सभी बड़ी और बहुराष्ट्रीय कं. को रु. 4 करोड़ की सड़कें, 12-14 से रु. 18 से 20 करोड़ में जालसाजों को गिरवी कर प्रति कि.मी. रु. 10 करोड़ का औसतन घोटाला किया और राष्ट्र की 7000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, जो पूर्व में जनता के लाखों करोड़ से बनाई और रखरखाव की जा रही थी, जालसाज डकैतों को लूटने के लिये 20 से 30 वर्षों के लिये गिरवी करके सौंप दी, अब प्रतिदिन यदि औसतन हजारों वाहनों से रु. 10/- प्रति कि.मी. की वसूले जा रहे हैं, अर्थात रु. 20 हजार प्रति कि.मी. के मान से रु. 1400 करोड़ की वसूली की जा रही है। जबकि सड़कें अभी न केवल कई तो बनी ही है, और जो बन गई हैं उन पर ढंग रखरखाव नहीं किया जा रहा है। जिसमें इंदौर-देवास पर इसका सच देखा जा सकता है, फर.09 से अग.12 हो जाने के बाद इंदौर-झाबुआ 192 कि.मी., गुजरात तक हर वर्ष 400 से ज्यादा वाहन चालकों की मौत हुई, इंदौर-सेंधवा पर वाहनों की पैसे देने के बाद भी सुरक्षित मार्ग न होने से हर दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इस तरह रु. 7 हजार करोड़ की वसूली में नेताओं का भी हिस्सा हैं, वही हाल म.प्र. में भी हैं, जहां 4000 कि.मी. की सड़कों में मात्र 700 कि.मी. सड़कें ही 4 लेन हैं, इसके विपरीत सब पर वसूली एक जैसी है वरन हर वर्ष 7% की दर वृद्धि भी हो जाती है जो कि हर तीन वर्ष में होनी चाहिए थीं, प्रतिदिन 500 वाहन× 10×4,000= 20 करोड़ रु. प्रति दिन अवैध रूप से वसूला जा रहा है।

फिर पेट्रोलियम खरीदी में प्रति 300 करोड़ बैरल प्रति दिन की खपत में मात्र प्रति बैरल रु. 100/- प्रति बैरल अर्थात 2 डॉलर डकारे अर्थात 6000 करोड़ रु. प्रति दिन प्रतिवर्ष रु. 21.9 लाख करोड़ प्रतिवर्ष, खाद में कृषि के लिये खरीदी में रु. 2000/- प्रति टन के हिसाब से 50 लाख टन में रु. 6000 करोड़ रु. बीटी, जीएम और हायब्रिड जो हर फसल जिसमें कपास, मक्का, तुअर, चना, सोयाबीन आदि के बीजों की खरीदी बिक्री में 10,000 टन बीज में मात्र रु. 10,000 प्रति टन का कमीशन कृषि मंत्री और मंत्रालय ने डकारा, बिजली खरीदी में रु. 0.10 पैसे प्रति यूनिट की निजी कं. से खरीदी में कमीशन में 1 लाख करोड़ यूनिट हर घंटे में टाटा, रिलायंस, जेपी, हिंडाल्को से म.प्र. व अन्य राज्यों ने खरीदी 24 घंटे में 24 लाख करोड़ युनिट में रु. 2.40 लाख करोड़ रु. प्रति दिन, 5 हजार लाख टन गेहूं निर्यात की मंजूरी गल्फ देशों व अन्य देशों के लिये दी गई, 2 रु. प्रति कि. के हिसाब से रु. 2000 प्रति टन, जो गेहूं रु. 13/- में खरीदा गया था, मात्र रु. 20/- प्रति किलो बेचा गया जिसे शासकीय खाते में रु. 161, 171/- प्रति कि. दिखाया गया तो फिर यूरेनियम प्रति टन, परमाणु माहियों जिनसे बिजली बनाने की योजना है, संवर्धित यूरेनियम, खरीदी में रु. 1 लाख प्रति टन भी डकारा गया तो 1000 टन प्रति वर्ष की खपत से कितना कमीशन होगा, अर्थात हर कदम पर लूट वसूली के हिसाब क्या सरदार घोटाला सिंग रु. 10 हजार लाख करोड़ रु. डकार रहे हैं। इसके बाद भी करोड़ों को बेरोजगार करने फुटकर व्यवसाय में विदेशी निवेश, वायदा व्यापार और बैंकों के सस्ते ऋणों से विदेशियों को बड़े-बड़े उद्योग लगाने के न्यौते, देश का धन विदेशियों को सौंपकर राष्ट्र की जनता को महंगाई का पुरुस्कार दिया जा रहा है।

मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने के लिये हर दिन 2 से 5000 को बांग्लादेशियों का प्रवेश असम से लेकर बंगाल तक सीमा सुरक्षा बल के लोग ही रु. 2 से 5000 लेकर करवा रहे हैं। जब असम के बोडो स्थानीय लोग भगाने की मांग करते हैं, तो वोट बैंक की खातिर स्थानीय लोगों की सुरक्षा तो दूर उल्टे ही इन विदेशियों की गारंटी दी जाती है। चमकाने धमकाने के लिये पूर्वोत्तर के लोगों को पूरे देश से खदेड़ा जाता है। इसके हित साधन में मुंबई में, हैदराबाद, पुणे में हिंसा फैलाकर हिन्दुओं को धमकाया जाता है। फिर कांग्रेस का तो पुराना खेल है जातीय हिंसा की आग में देश को झोंककर, नोट और वोट बैंक बढ़ाना और सहायता व पुर्नवास के नाम पर सहानुभूति बटोकर वोट और अरबों नोट बटोरना।

महाधूर्त वित्तमंत्री को उनके लूट-खसोट के पापों ने उनकी आत्मा को झकझोरना शुरू कर दिया तो राष्ट्रपति बन गये, स्वाभाविक था पद रिक्त हो गया तो पुनः वह महामक्कार धूर्त चीटअंबर पुनः वित्तमंत्री बना दिया गया जो पूर्व से ही अनेकों भ्रष्टाचारों के सागर में गोते लगा रहा था। हर कदम-कदम पुनः कमीशन डकारने के चक्कर में महंगाई भी बढ़ाई जायेगी और करों का बोझ थोपा जायेगा और लाखों-करोड़ कमीशन के रूप में बहुराष्ट्रीय कं. बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा कर डकारा जायेगा, जिसका भुगतान जनता को ही करना होगा। तंत्र में बैठे सरदार घोटाला सिंग ने सेना की खरीदी में, परमाणु बिजली संयंत्रों को लगाने, परमाणु ईंधन खरीदने, स्वास्थ्य में दवा खरीदी और आयात करने, बहुराष्ट्रीय दवा कं. को पैर जमाने, देशी दवा उद्योगों को समाप्त करने, औषधि परीक्षण की विदेशी दवा कं. को पूरे देश में कभी भी, कुछ भी कभी परीक्षण करने की छूट देने, आटोमोबाइल कं. को भारत में अपने उत्पादन और माल बिक्री करने, देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर बहुराष्ट्रीय कं. को देश में खाद्य से लेकर पानी का व्यवसाय करने की छूट देने और देशी 5 से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने के षड्यंत्रों में,ल शिक्षा के नाम पर कुकुरमुत्तों की तरह इंजिनियरिंग, चिकित्सा प्रबंधन, कम्प्यूटर आदि के स्तरहीन कालेज खोलने, एयर इंडिया के लिये विमान खरीदी में अरबों के कमीशन, खनिजों के वैध-अवैध खनन, भूमाफियाओं को पूरे देश में कालोनियां काटने में कानूनों से परिवर्तन करने, महिला बाल विकास, रेल मंत्रालय में पूरे देश के प्लेटफार्मों के ठेके देने, इंजिनों मालवाहन और यात्री वाहक कोचों, पटरियों के रखरखाव, साफ-सफाई के निजी क्षेत्र में ठेके देने, बिजली क्षेत्र में देश के सभी राज्यों के विद्युत मंडलों को खंड-खंड कर कंपनियां बनाने, उत्पादन, वितरण संवर्दन को निजी क्षेत्र में देकर देश में अंधेरा करने, हर वर्ष दो से तीन बार बिजली की कीमतें बढ़ाकर राज्यों की जनता को लुटवाकर, जल-थल, परिवहन सेवाओं में निजीकरण करवाकर जनता को लूटने, शहरी विकास, मंत्रालय की योजनाओं, जलसंसाधन विकास की योजनाओं, खाद्य वस्तुओं यथा शक्कर, तेल, अनाज, दलहन, तिलहन को ऊंची कीमतों निर्यात में मोटा अरबों करोड़ का कमीशन हजम कर तक भी पैदा करने, फिर ऊंची कीमतों पर सड़ा, पुराना, स्तरहीन माल विदेशों से ऊंची कीमतोंप र आयात करने में मोटा अरबों करोड़ की कमीशन डकारने जैसे हजारों मामलों में अरबों लाख करोड़ का कमीशन हजम करने वालों को राष्ट्र की जनता को समृद्ध करने की चिंता नहीं, सत्ताधीशों को तीन तेरह, नौ अठारह की चिंता और उधेड़बुन ज्यादा सताती है। वोट के लिए राष्ट्र को गिरवी और बेचने से भी कोई परहेज किसी सत्ताधीश को कभी नहीं रहता

अब जब चुनाव सिर पर हैं तो वोट के लिए अजा जजा को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिये संविधान की समानता की मूल भावना का गला घोंटकर संविधान में 250 से ज्यादा संशोधन करने के बाद पुनः संशोधन से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। जिस भाजपा को पूरे देश में 1980 से सवर्णों ने नोट और वोट देकर जीवित रखा, वही भाजपा न केवल म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक व पूरे देश में उनके अधिकारों के विरुद्ध पुनः शूकरों की फौज कांग्रेस अंग्रेजों की अवैध औलाद के साथ मिलकर संशोधन करवायेगी, जब लोक, जालसाज तंत्र का चुनाव करके तंत्र को नोंचने के लिए छोड़ देता है, तो कैसे तंत्र की मजबूती सभी डकैत बनकर लूटने में लगे हैं, तो कैसे लोक अपनी समृद्धि की कामना करेगा।

गीत गुलामी का गायेंगे,

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब जहां जैसा राजा मिला कभी हारे-कभी जीते, पर अब तो हार जीत के लिये तोप और बंदूके भी नहीं चलानी पड़ेगी, पहले स्व. राजीव गांधी से शादी करके पिछाड़ू दरवाजे से सोनिया घुस ही आयी है, यहां के कांग्रेसी गुलाम उसे प्रधानमंत्री बनाने पर आमादा थे ही, गुलामी बिना एक बहाने ही आ गई है। अब वह इटालियन सामने से नहीं सत्ता की कुर्सी को विदेशी रिमोट से चला रही है और शायद जन,गण,मन करवा कर अधिनायकों की जय करवा रही है, इसलिये हमारे कांग्रेसी सत्ताधीश श्वानों ने अपना धन इसीलिये विदेशों में रखा है कि अगर कुछ भी हो तो अपना परिवार लेकर जाकर विदेशों में बस जायेंगे, यदि रु. 300 लाख करोड़ का धन विदेशों में जमा हैं, तो विदेशियों ने तो रु. 75 लाख करोड़ भी भारत में निवेश नहीं किया है फिर भी गुलामों की तरह रहना पड़ेगा।

सरकार और बहुराष्ट्रीय कं. का षड्यंत्र

पृष्ठ 8 का शेष

वो पुरुष नामर्द और स्त्रियां बांझ होकर निकल रहे हैं। केंद्रीय औषधि प्रशासन ने आनंद राय के सूचना अधिकार में जो जानकारी दी हैं, वो वास्तविक मातों की मात्र 0.001% से ज्यादा नहीं जो जानकारी दी है उसमें देश के हर प्रदेश में औषधि परीक्षण से हजारों की मौत को स्वीकार किया गया है। भारत सरकार और उसके व राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सरकार और बहुराष्ट्रीय दवा कं. का उद्देश्य ही है कि अधिकांश युवा या तो मर जाये या इसके विपरीत भी जीवित रह जाये तो नामर्द और बांझ बन कर गुलामों की भांति जीवन जिये और उसे वोट देकर उसके सत्ता प्राप्त कर लूटने की व्यवस्था करते रहे, उसके खिलाफ न तो हल्ला मचायें, न उसके शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकें, चाहे फिर 2 जी, कोयला घोटाला करें, बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसेड़कर पूरे देश में वोट बैंक मजबूत करें, मंदिरों-मस्जिदों में बम फुड़वाकर हिन्दुओं को प्रताड़ित करें, निर्दोषों पर जुल्म ढाये, साध्वी प्रज्ञा को पकड़े पुलिसियों से उसका यौन शोषण करवाये, हिन्दू नामर्द, कभी कानून के डर से, कभी प्रताड़ना के डर से, कभी किस्मत को लेकर टुकुर-टुकुर ताकता रहे अपने आकाओं को, पर न आवाज उठाये न चिल्लाये, वही हो रहा हैं।

क्यों थोपे जाते है कानून, जनता के सीने पर क्यों नहीं प्रकाशित किये लागू करने से पूर्व

ब्रिटेन में पास किये जाने से पूर्व प्रकाशित कर जनता की राय देखी जाती है।

भारत में कानून बनाना और जनता पर थोप देना भारतीय सत्ताधीशों का अपने हित साधने का शौक बन चुका है। जो कि वोटों की राजनीति से प्रेरित होने के साथ ही अब वर्तमान में जनता को हांकने और अपने हित साधन का हथियार बना दिये गये हैं। वैसे भी एक बुजुर्ग वकील के साथ गपशप करते समय उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कानून के बारे में कही थी, कि कानून धूर्त सत्ताधीशों के बनाये शब्दों के मायाजाल हैं, जो अपने हितों के साधने और निरीहों के शोषण के पोश हथियार हैं। शब्दशः सही प्रतीत होते हैं। सन् 1965 के बाद भारत में जितने भी कानून बने उनमें जनहित कम और सत्ताधीशों के स्वहित ज्यादा थे, और अधिकांश वोटों की राजनीति से प्रेरित थे,

भारत में वैसे भी अधिकांश कानून ब्रिटीश सरकार द्वारा बनाये गये ही अभी तक चल रहे हैं। जबकि ब्रिटीशर्स ने कानून अपनी सत्ता के स्थायित्व और गुलामों को हांकने और विशुद्धतः अपनों के पोषण और भारतीय जनता के शोषण के लिये ही बनाये थे।

राष्ट्र की आजादी के 65 वर्ष बाद भी उन आधारभूत कानूनों में न केवल बदलाव नहीं किया जा सका, वरन तात्कालीन सत्ताधीशों से लेकर वर्तमान सत्ताधीशों तक सभी को कानून न केवल उपयुक्त लगे, वरन सत्ता चलाने के लिये और अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के पोश हथियार भी तैयार में हाथ लग गये, यही कारण था कि धूर्त कांग्रेस गिरोह के शातिर और धूर्त मंत्रियों ने जनहितों के नाम पर अपनों का पोषण और जनता का शोषण कर अरबों लाख करोड़ भारत से एकत्रित कर अंग्रेजों की भांति अंग्रेजों के स्थान पर स्वयं ही विदेशी बैंकों में जमा करवाते रहे, और वर्षों तक जनता को खबर नहीं हुई।

भारत के धूर्त सत्ताधीशों की एक मानसिकता यह भी रही है कि जो भी तथ्य, कानून, जनहित के हों और उनके अहित के हों, या उनकी सत्यता को प्रगट कर भविष्य में उनका अहितकारी हो, वे कदापि स्वीकार नहीं करते, वे उन्हीं तथ्यों, कानूनों और कार्यों को स्वीकार करते हैं जो कि भविष्य में उनके लिये हितकारी आय का स्त्रोत बन सकते हो, वोटों की राजनीति में उन्हें ज्यादा वोट दिला सकते हो, वो उसे बिना बताये, जनता पर थोपने के लिये एक पैर पर तैयार रहते हैं। सत्ताधीशों ने अपने मोटे कमीशन और उससे मोटी आय के चलते कई कानून बनाये, जिसमें विश्व की अनेकों बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कं. के हितों के संरक्षण किये गये। बदले में मोटी रकम ऐंटी गयी, जिसमें खेती के लिये और उस पर कब्जे के लिये बीज अधि., खाद अधि., कीटनाशक अधि. महत्वपूर्ण थे जिसके बाद उन बहुराष्ट्रीय कं. ने अपने राष्ट्र की कृषि की बर्बादी के लिये अपने खाद, बीज और कीटनाशक बेचें उसी श्रेणी में थी युनियन कार्बाइड, बाद में हर साल कानून लादने का सिलसिला चल निकला। राष्ट्रीय कं. में टाटा ने दांव खेला और आयोडीन नमक 1972 बनवाया और डूबती टाटा केमिकल्स की नैया पार लगाई। अब पूरे देश में 40 वर्षों से पूरे देश में आयोडीन नमक बेचकर जिन्हें आयोडीन की जरूरत नहीं है, तो भी उन्हें जबरदस्ती आयोडीन नमक खिलाकर बीमार बनाया जा रहा है। जबकि देश में मात्र 30 से 40 लाख लोगों जो की हिमालयीन तराई के क्षेत्रों में आते हैं। जिन्हें घेंघा रोग हो जाता है जो कि मात्र 0.25 से 0.4 ही होंगे कुल आबादी का। बदले में स्व. इंदिरा गांधी ने टाटा से मोटी रकम ऐंठ कर 55 करोड़ भारतीय जो अब 125 करोड़ हो गये हैं, से उस समय 10पै. किलो के नमक रु. 2 और अब 50 पै. किलो के नमक के रु. 15 वसूले जाते हैं। बदले में रसायन मंत्री मोटी रकम हर वर्ष डकार लेता है। तब से लेकर अभी तक जनता को बिना बताये जबकि कानून बनाने का आधार से लेकर उसके कारण, भविष्य में उसके लाभ और हानि के साथ ही उस पूरे कानून को प्रकाशित कर उस पर जनता की राय ली जानी चाहिये, जबकि ब्रिटेन में कानून बनाने का आधार, उसके कारण, उसके लाभ-हानि के साथ ही पूरा कानून समाचार पत्रों में प्रकाशित कर जनता की राय ली जाती है, वहां इसलिये सत्ताधीश मनमर्जी या अपने हितों के लिये कानून नहीं बना सकते, जबकि आजादी के बाद से भारत में 200 से ज्यादा कानून बिना जनता को कानोंकान खबर किये ही थोप दिये गये, जिनमें अधिकांश सामाजिक कानूनों में ब्राह्मण, बनियों, राजपूतों आदि स्वर्ण वर्ग को ही निशाना बनाया गया है। कांग्रेसियों के बनाये अधिकांश सामाजिक कानूनों में मुस्लिम परस्ती के साथ ही उनके वोटों को अपने खाते में बनाये रखने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार आदिवासियों और दलितों के वोटों को अपना बनाये रखने के लिये अस्पृश्ता निवारण अधि. दलित एवं आदिवासियों के लिये प्रताड़ना एवं उत्पीड़न अधि. भी इसीलिये थोपे गये, जबकि इन सत्ताधीश धूर्तों को करों के रूप में जो कुछ मिलता और जिस पर उन्हीं स्वर्णों के विरुद्ध शुरू से ये षड्यंत्र रचकर जातिवादी, वैमनस्यता फैलाने की ये कुचेष्टायें करते आ रहे हैं।

लक्षित हिंसा अधि. 2011 में तो इन्होंने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों पुलिस में कार्यरत स्वर्ण हिन्दुओं को भी 10 वर्ष तक की सजा व्यवस्था कर दी है। सत्ताधीश धूर्तों की फौज को इन सबका तब अहसास होता है, जब ये स्वयं इसके लपेटे में आते हैं और जब जाकर जनता के दुख दर्द समझ में आते हैं। आखिर भारत की जनता की घोर स्वार्थी मानसिकता ने हजारों वर्षों की गुलामी को भोगा है। फिर वर्तमान सत्ताधीश धूर्त अपनी कमाई और कमीशनखोरी के चलते उसने बहुराष्ट्रीय कं. को राष्ट्र की जनता को फिर इनके हवाले करने के लिये हर सत्र में नये कानून इनके पक्ष में बनाये जा रहे हैं। जिसका एक उदाहरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 है। जिसके अंतर्गत सारी खाद्य सामग्री को जो न केवल स्तरहीन होगी वरन मिलावटी होने के बाद भी पैक करके बेची जायेगी। सभी कोल्ड ड्रिंक्स में मेलाथियान जैसे विष मिलाकर कैफीन और शकर के मिश्रण को युवाओं को पिलाकर भरी जवानी में उन्हें न केवल नपुंसक वरन किडनी और हृदय का रोगी भी बनाया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार और सत्ताधीश धूर्त देश पर कोई भी कानून थोपने से पहले जनता से नहीं पूछेंगे, क्यों प्रकाशित नहीं करेंगे कि किसी भी अधिनियम को लाने का आधार और कारण क्या है? उससे जनता को क्या हानि-लाभ होंगे, प्रकाशित नहीं किये जाकर जनता की राय जानी जाती है। क्या जनता केवल वोट देने की मशीन है। उसके हित-अहित के बारे में एसी कमरों में बैठकर क्या नीतियां और कानून बनाये जाते हैं।

यदि ये लोकतंत्र है, तो लोक द्वारा चुने गये तंत्र और गण उससे क्यों नहीं पूछते कि आपके हित-अहित में ये कानून लागू किया जा रहा है। इसके बारे में यहां सूचित करें, कि इसमें क्या कमी है। संशोधन है।

भारत के सत्ताधीश धूर्त सत्ता में आते ही सत्ता को अपने बाप की जागीर समझने लगते है। फिर उसे नोंचने-मोटी कमाई करने के लिये, जालसाजियों, षड्यंत्रों की रचना करते हैं। इससे अगर पेट नहीं भरता तो फिर अपने हितों के पोषण और निरीहों के शोषण के लिये कानून बनाते हैं।

यदि भारत में सचमुच लोकतंत्र है तो क्यों नहीं किसी भी कानून को थोपने से पहले जनता उसके प्रकाशन की मांग क्यों नहीं करती, चाहे तो केंद्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का या क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर का, जिसमें उसके कारणों आधार के साथ उसकी मंशा, उसका पूरा ब्यौरा, लाभ-हानि के बारे में जनता की राय क्यों नहीं ली जाती है। जनता को इसकी मांग करनी चाहिये, ताकि जनहितों पर सत्ताधीश कुठाराघात ही कर सकें।

बिल लेने की आदत डालने प्रोत्साहन जरूरी

बिल लेने पर जनता को दिये जाये इनाम

इंदौर। म.प्र. के वाणिज्य कर मुख्यालय को चाहिए कि वह व्यापारियों और विक्रय फर्मों से उचित तरीके से वाणिज्य कर वसूलने के लिये जनता को हर खरीदी पर बिल लेने की आदत डालने के लिये पक्के बिलों की मूल प्रति वाणिज्य कर, हर वृत्त के बाहर लगे डिब्बों में डाले और हर वृत्त हर माह रु. 50,000/-, रु. 30,000/-, रु. 10,000/- और रु. 5,000/- के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दो सांत्वना पुरस्कार देगा, इस प्रकार 80 वृत्तों में रु. 80 लाख प्रति माह के पुरस्कार बांटकर कम से कम पूरे म.प्र. स्तर पर रु. 100 से 1000 करोड़ का घर बैठे बिना कुछ किये अपनी आय बढ़ा सकता है।

छत्तीसगढ़ में है तो म.प्र. में क्यों नहीं? 10 करोड़ खर्चा कर रु. 100 करोड़ की हो सकती है आमदनी जनता बिल लेगी तो व्यापारी कर भरेगा

बिल पक्का हो, उसमें टिन नं. डला हो, जब जनता अपने विक्रेता दुकानदार से पक्के बिल की मांग करेगी तो विक्रेता अपने आप दहशत में आ जायेगा, फिर दो नं. के बिल नहीं काट सकेगा। जो लाखों बिल आयेंगे उस दुकानदार के खातों से जांच करने का भय व्यापारियों को हर काम पक्का करने पर मजबूर कर देगा, स्वाभाविक है, पक्के बिलों का हिसाब भी पक्का करना पड़ेगा, साथ ही कौन व्यापारी कितने बिल काट रहा हैं, उससे उसका टर्नओवर या कुल लेन-देन की बिक्री उसके बिल नं. के आधार पर लगाई जा सकेगी, तीन साल तक बिलों को डालने वाले उपभोक्ताओं को पुरुस्कार देने के फलस्वरूप जनता को बिल लेने की आदत पड़ जायेगी, जिसकी दहशत में व्यापारी अधिकांश कार्य 1 नं. में करने लगेंगे।

पुरुस्कार प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं द्वारा डाले गये बिलों में बिल एक माह से ज्यादा पुराना न हो। उसमें न केवल टिन नं. वरन व्यापारी की बिल बुक का नं. और सीदा बिल क्र. भी हो और बिल की मूल प्रति ही हो, फोटोकॉपी डिब्बों में न डाली जाये, उसमें विक्रेता का पता स्पष्ट हो, इंदौर जैसे नगर में जहां वाणिज्य कर के 15 वृत्त कार्यरत हैं। बिलों बे बाक्स में जो नगर के अनेकों शासकीय कार्यालयों में लगाये जाकर इकट्ठे किये जायें और वृत्तानुसार छांटकर संबंधित वृत्तों को सौंप दिया जाये। बिलों में क्रेता का नाम, पता व मोबाइल नं. स्पष्ट लिखा हुआ हो, कम से कम रु. 100/- का बिल हो, वह किसी भी सामग्री का हो, लॉटरी में इनमा निकालते समय इन सब तथ्यों के आधार पर हर माह हर वृत्त में 5 पुरस्कार बांटे जाये,

इससे जनता खरीदी करते समय पहले ही बिल बनाने, उसमें टिन नं. देखने के साथ बिल बुक और उसका क्र. भी देखेगी, इस प्रोत्साहन से व्यापारियों को हर माल का बिल तो देना ही पड़ेगा, साथ ही सारे कागजात भी पक्के बनाने होंगे, बाद में इन्हीं बिलों की पूछताछ कभी भी वाणिज्य कर निरीक्षक से लेकर कराधिकारी तक 6 माह में कर यह जान सकेगा कि व्यापारी ने जो बिल दिया है, उसका नं. क्या था, उसका हिसाब किताब कहां किया गया है, उस पर कर चुकाया गया है या नहीं, नहीं चुकाया है तो तीन गुना दंड लगाकर वसूला जाना चाहिये। जिस विक्रेता के पास इन बिलों के लेने-देने का हिसाब नहीं पाया जाये, उसका स्वकर निर्धारण व्यवस्था से बाहर कर खाते जब्त कर कार्यवाही की जाना चाहिये। इससे न केवल विक्रेताओं, क्रेताओं वरन सरकार को भी सच्चाई जानने और जनता को भी उसके अधिकारों के प्रति सचेत करने का मौका मिलेगा।

बजाज ने 50 वर्षों में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा बर्बाद की पेट्रोल पर

सारी दोपहिया वाहन कंपनियां झूठे विज्ञापनों से लूटती है जनता को

बजाज के स्तरहीन स्कूटर और बाइक्स ने चालकों को किया परेशान

बजाज कं. जो राष्ट्र की अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता कं. रही हैं, भारत की एक नं. की जालसाज, झूठी, बतमीज कं. भी रही हैं, जो औसत प्रति ली. सीसी100, प्लेटिना और डिस्कवर के बारे में लिखा और विज्ञापन दिया जाता है, जैसे कि 101 कि.मी. प्रति लि. जबकि कभी भी मुश्किल से 45-50 से ज्यादा नहीं मिलता, दूसरी ओर 1940 से देश में इस राहुल बजाज की कं. ने जो वेस्पा, प्रिया, बजाज कब, चेतक स्कूटर बनाकर देश में करीब डेढ़ करोड़ स्कूटर बेचें हरामखोरों और जालसाजों ने 40 वर्ष तक उसमें कोई अनुसंधान तो किये ही नहीं वरन उसकी मूलभूत कमियों में भी सुधार नहीं कर सके यहां तक कि उन स्कूटरों में औसत मिलने की बात तो दूर सिटिंग तक ढंग से नहीं कर पायें जिससे 70% 40 वर्ष से ऊपर उम्र के वाहन चालकों को रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता था, दूसरी ओर 70% से अधिक स्कूटर चालकों को किक लगाने से यांत्रिक गड़बड़ीयों के कारण उसमें कई बार 50-50 किक तक लगाना पड़ती थी सबके घुटने ढीले कर दिये, शायद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने भी वर्षों तक स्कूटर चलाने के कारण ही ढीले हो गये थे, बाद में प्रधानमंत्री रहते उन्होंने घुटने बदलवाये जिसका मसखरों ने सार्वजनिक रूप से मजाक बनाया था, करोड़ों लोग जो बेचारे जवानी भर स्कूटर चलाते रहे हैं, बुढ़ापे में इन में किक लगाने से घुटने के दर्दों को भोग रहे हैं। पर इस शूकर राहुल बजाज को इससे क्या फर्क पड़ता है।

सन् 2000 के बाद इसने स्कूटरों का उत्पादन बंद कर दिया क्योंकि बाजार में अनेकों नये उन्नत किस्म के स्कूटर और मोटर सायकलें बाजार में आ गई थीं, स्वाभाविक था अपना आस्तित्व बरकरार रखने के लिये ये मोटर सायकल के बाजार में उतरा, परन्तु बाइक्स के बाजार में भी वही जालसाजियां की गई, जबकि वास्तविकता इन हरामखोरों को मालूम थी, बाइक्स में भी ज्यादा औसत दिखाने के चक्कर में 25% मीटर ही तेज कर दिये गये ताकि औसत ज्यादा दिखे, सीसी 100 का औसत विज्ञापनों में प्रकाशित किया 101 कि.मी. प्रति लीटर 25% भी तेज था तो स्वाभाविक रूप से आ गया, 75 कि.मी. प्रति कि.ली. जो कि प्रयोगशाला की स्तरीय स्थिति में था, पर सड़क पर उसने और प्लेटिना ने 50 से ज्यादा कभी नहीं दिया, दूसरी ओर मोल्डेड पहिये डाल देने से गाड़ी 70% के ऊपर जाने पर कंपन करने लगती है, पंचर हो जाने पर अनियंत्रित होकर लहराने लगती थी, वर्तमान में जिस डिस्कवर पर 107 कि.मी. का औसत लिख रहे हैं। वह भी 45-50 से ज्यादा नहीं देती, शोरूम पर दिखाया तो कहा हमने ठीक कर दिया है अब 60-70 कि.मी. का औसत देगी, पर 45-50 से ज्यादा नहीं चली, रु. 45000/- की गाड़ी में इतनी घटिया बैट्री लगाकर बेची जा रही है, जो 300-400 रु. की है, जिससे तेजाब झलकता है, जो कवर लॉक जला देती है और गाड़ी की बॉडी भी खराब कर देती है, लेने के 13वें दिन ही एक्सीलेंटर वायर टूट गया, जिसमें स्कूटरों वाली ठेसी या घुंडी वाला तार लगाया गया था, अर्थात हरामखोर, जालसाजों ने जो बत्तमीजियां स्कूटरों के क्लच, गियर और एक्सीलेटर वायरों में 40 वर्ष तक ठेसी वाले तार लगाकर वाहन चालकों को मुश्किलें और परेशानियां खड़ी की थी और हर 1000-2000 कि.मी. में वायर बदलवाने और मिस्त्रियों की चरणदासी की व्यवस्था की थी, इन गंदे नीचों ने डिस्कवर के क्लच और एक्सीलेंटर वायरों में भी वही फिर दोहराया ताकि सारे काम-धाम छोड़कर मिस्त्रियों के चक्कर काटे, इसके साथ एक्सीलेटर के ऐसे सॉकेट बनाये कि वो कभी भी अटककर पलट जाता है,

(शेष पृष्ठ 5 पर)

साप्ताहिक समय माया

जनता से वसूला व्यापारियों ने, शासन ने स्वकर निर्धारण में छूट दी

जालसाजों को आईटीआर और मनोरंजन कर से लुटाया

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत मनोरंजन कर का पुर्नभुगतान

म.प्र. के विक्रय कर बनाम वाणिज्यिककर विभाग की कार्यशैली और शासन की नीतियां एक दूसरे के विपरीत जा रही है। शासन हर बजट में वस्तु में वस्तुओं पर करकी दरें बढ़ाता-घटाता है। स्वभाविक है, वाणिज्यिककर को शासन की नीतियों का पालन करना है। बजट में निश्चित की गई दरों से विक्रय पर वाणिज्यिक कर वसूलना है, पर इसके विपरीत व्यापारी तो जनता से उस दर पर हर सामान की बिक्री पर म.प्र. का वाणिज्यिककर वसूल लेता है। स्वभाविक है, जनता से व्यापारी द्वारा वसूला गया हर प्रकार का कर शासन की राजस्व आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी तरफ शासन पिछले 4-5 वर्षों से उसी व्यापारी को स्पष्ट निर्धारण कर कर जमा करवाने की छूट दे रहा है, जिसमें 99 प्रतिशत व्यापारी कर चोरी कर मात्र 10-20 प्रतिशत कर ही जमा कर रहा है। अन्य वाणिज्यिक अधिकारी-कर्मचारी किसी भी व्यापारी से बिना कुछ पूछे ताछे 98 प्रतिशत तक व्यापारी द्वारा मर्जी से जमा किया कर ही स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

इस प्रकार शासन व्यापारियों पर तो हर वर्ष बजट में करारोपण की दरें तय करके व्यापारियों को विक्रय पर जनता से कर वसूल करवा लेता है। दूसरी तरफ उन्हीं व्यापारियों को खुली छूट देता है कि वे जितना चाहें स्वयं निर्धारित कर विक्रय बनाम वाणिज्यिक कर जमा कर दें। स्वभाविक न केवल एकल, साझेदारी, निजी कम्पनी, शेयर होल्डिंग कं., संयुक्त उपक्रम क्र., तक खुलकर एक नं., दो नं., तीन नं. के खाते रखती है। एक नं. में केवल शुल्क बैंक से किया लेनदेन जिस पर सारे टेक्स तथा विक्रय के केन्द्रीय विक्रय कर, एक्साईज, आयकर आदि चुकाने हैं। दो नं. में तो सारा व्यवसाय जिसमें सारा नगद रोकड़े में कच्चे बिल पर लेन-देन तो होता है, परन्तु लेन-देन पूरा हिसाब किताब रखा, तीन नं. में बैंक के ऐसे खातों से चलाया जाता है, जिसका वैधानिक रूप दिखाने का अस्तित्व होता है पर उसमें वाणिज्यिक कर प्रवेश कर केन्द्रीय विक्रय कर के बिल जनता से वसूला तो जाता है, परन्तु सरकार तको ऐसे लेनदेन की हवा ही नहीं लगने दी जाती। जरूरत पड़ने पर उसकी वैधानिकता भी सिद्ध की जा सके ताकि कोई भुगतान न मिलने पर कानूनी अस्तित्व एक नं. में स्थानांतरित किया जा सके। स्वाभाविक है इसमें किसी प्रकार का वसूली के बाद भी कोई शासकीय क्रेताओं की बाध्यता नहीं होती। व्यापारियों को ये सारपी चालाकियां उनके कर सलाहकार बताया करते हैं। वैसे भी व्यापारी भी समय के साथा स्वयं कर चोरी के विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे सलाहकारों को केवल वे ही सब बताते हैं। जिनमें वो कर चुकाने की इच्छा रखते हैं और आय को एक नं. में दिखाकर पूंजी खड़ी करना चाहते हैं। जनतो बेचारी जो शासन ने कररोपण किया है, वह चुकाने के लिए बाध्य है। अब जबकि वाणिज्यिक को तो विभागीय आदेश है कि किसी भी व्यापारी से कोई पूछताछ खातों की देखभाली कुछ न को तो जो इच्छा से जमां कर दे उसको स्वीकार करों।

अर्थात स्वयं शासन जनता को दोनों तरफ से मारता है कि जनता के जेब से तो कर का पैसा वसूला गया, जब वह शासन के खाते में नहीं पहुंचा तो उसने नए करारोपण कर दिए फिर जनता ही लुटी से सेवाकर के दायरे को बढ़ाकर ठीक है कि तो केन्द्रीय कर है। मात्र 24 सेवाएं छोड़ी बाली सब पर कर थोप कर जनता को हर कदम लूटा जा रहा है। दूसरी ओर वह धन जनता और देश के विकास कार्यों में भी नहीं लगा तो भी जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिला तीसरी ओर वह कालाधन मुद्रास्फीति बढ़ाने में अहम भूमिका अदाकर रहा है। महंगी धातुओं, जमीनों, वस्तुओं के व्यापार में वो काला धन लादकर हर वस्तु की कीमत बढ़ा रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्य यह है कि यदि जब सम्पत्तिकर दाताओं को रखकर निर्धारण ही करना है तो विभाग में इतने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या जरूरत है। जितना व्यापारी भर देगा उतना शासन के खाते में कभी क्या जरूरत है, जितना व्यापारी भर देगा उतना शासन के खाते में पहुंच जाएगा, क्यों जब रसीद फार्म 49, सी फार्म और अनेकों फार्म भरने जमा करने की ओपचारिकताएं निभाने की भी क्या आवश्यकता है, जब आनलॉइन सारा कार्य हो ही रहा है, शासन घोषणा कर ही देता है बजट सत्र में की इस वस्तु पर इतना कर देना है, दूसरी ओर पूरे प्रदेश में एंटी इवेजन ब्यूरो बैठा ही है। तो महीनों की ट्रांसपोरियों से बड़े कर चोरों से वसूली ही कर लेता है और महीना भी पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर मंत्री संत्री तक पहुंच ही जाता है। धर पकड़ ट्रक रोकना आदि कर के उनके और सचिव, प्रधान सचिवों के राज्यों की भी व्यवस्था हो ही जाती है, वो बात अलगहै कि जब इन हरामखोरों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जाती है तो उपायुक्त दलों कानून विरुद्ध दलीलें देते हैं कि हमें इस आदेश के तहत छूट मिली हुई है। पहले लिखते थे कि पत्र क्र. एफ. 11-39-2008-सूअअ-1-9 दिनांक 27-08-08 में म.प्र. सरकार सा.प्र.वि.सू.अ.अ. कक्ष वल्लभ भवन भोपाल म.प्र. ने हमें सूचना के अधिकार 05 में जानकारी देने से मना किया है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग और एंटी इवेजन ब्यूरो में अधिकारियों के सारे लेखे-जोखे पिता की जागीर हो। यदि जनता से धन वसूल रहे हो और जनता के धन से वेतन लेकर कार्यकर रहे हो तो हराम खोरों जानकारी देने में क्या परेशानी है या अपने कुकर्मों से ही डर लग रहा है। वैसे भी सारे प्रदेश में जो महाभ्रष्ट थे, उन्होंने न केवल इंदौर के वरन् सभी सभी एंटी इवेजन ब्यूरो में धन खर्च करके ही वहां लूटने, खाने और खिलाने के लिए ही अपनी पदस्थापना करवाई है। चाहे तो उपायुक्त करोसिया हों सीटीओ निशा चौहान हो या में उपायुक्त भदौरिया हो, स्वभाविक है। धन खर्च करके पद स्थापना प्राप्त की है तो कमाई करने के लिए ही ली है. यदि ये हरामखोरों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी दे देतो सब पर लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की जांच बैठा दी जाएगी।

यथा जब एंटी इवेजन ब्यूरो वसूली करना और शासन के खाते में 1-2 प्रतिशत धन पहुंच ही जाता है और फिर दूसरी ओर स्वकर निर्धारण हो रहा है तो विभाग के सारे अधिकारियों को दूसरे विभागों में अंतरिक कर दिया जाना चाहिए।

1 अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक कर मनोरंजन कर भी दे दे दिया गया है। इसमें पूर्व में आबकारी विभाग भी अरबों रुपए के घोटाले कर चुका है। नए विनियोजन पर निर्माण के नाम पर मल्टीप्लेक्स टॉकिजों को 5 वर्ष की मनोरंजन कर से छूट मिली थी। इसके विपरीत पूरे प्रदेश में नए-नए बने मल्टीप्लेक्सों ने शासन से खुदका फायदा तो अवश्य उठाया परन्तु जनता 20-30 प्रतिशत मनोरंजन कर के नाम पर खुलकर वसूली करते रहे और कुछ मल्टीप्लेक्स वालों ने टिकिट कितने भी भेजे। पूरा तो किसी ने भी जमा नहीं किया पर 50-60 प्रतिशत मनोरंजन कर का भुगतान आबकारी को किया। बाद में छूट का लाभ लेने के लिए शासन से कहा, तो आबकारी उपायुक्तों, आयुक्तों ने उस जनता से लिए गए धन लौटा भी दिया। सभी अप्रत्यक्ष कानूनों यथा विक्रय कर, कस्टम अधिकारी, मनोरंजन कर जो जनता से वसूलता है, यदि वह व्यापारी ने शासन को जमा कर दिया जाता है तो शासन के कर के नाम से वसूला गया है, इसलिए शासन की सम्पत्ति है, इसलिए वाणिज्यिकर वेट आबकारी आदि में नियमानुसार राजसात कर लिया जाता है। पर इसके विपरीत म.प्र. अनेकों मल्टीप्लेक्स वालों को कर लौटा दिया जबकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्वन स्टोन्स मल्टीप्लेक्स विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सरकार 2012 में स्पष्ट निर्णय दिया था कि चूंकि यह कर जनता से वसूला गया है और उन्हें नहीं लौटाया जाना चाहिए। इसलिए इस धन को लौटाने की अपेक्षा जनहित के कार्यों में स्वयं शासन ट्रस्ट बनाकर गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के हित में सदुपयोग करे अप्रैल 10, 11 से वाणिज्यिककर के पास आने के बाद यहां भी भ्रष्ट अधिकारियों ने औने-पौने कर मल्टीप्लेक्स वालों को धन लौटाया, श्री अजमेरा ने सीधे ही इस धन लौटाने की कहानी इसलिए प्रधानसचिव से सूचना अधिकार में मांगी थी, जिसने उसे पूरे प्रदेश के हर वृत्र और उपायुक्त को भेजकर इतिश्री कर ली, जबकि सारा संक्षिप्त वितरण मंत्रालय के पास भी होगा। यह निर्णय स्पष्ट करता है, जनता से व्यापारियों द्वारा वसूला गया धन शासन का है। उसकी पूरी वसूली होना चाहिए, जिसके लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त से लेकर अधिकारी, बाबू, निरीक्षक और चपरासी न केवल जिम्मेदार है वरन् वह वेतन भी इसी कार्य के लिए ले रहा है। कैसा और क्यों स्वकर निर्धारण और क्यों एंटी एवेजन की छापे मारने और वैध-अवैध वसूली की ठेकेदारी।पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जो वाणिज्यिक कर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इससे वाणिज्यिकर में हर वर्ष बढ़ोत्री हो रही है। जबकि सच यह है कि स्वकर निर्धारण से और वेट से कर आय में कमी आई है। वेट लागू करने की भरपाई से भी केन्द्र सरकार ने मनाकर दिया है। दूसरी ओर जिस प्रकार मनोरंजन कर वापस लौटाया गया, उसी प्रकार आईटीआर में 5000 करोड़ से ज्यादा प्रदेश सरकार वेट के कारण लुटा रही है। जबकि आईटीआर में प्रदेश सरकार ही लूट ही रही है और सेकड़ों जालसाज फर्मे इसका लाभ उठा रहा है। श्री कृष्ण प्रोफाइल्स जिसने करोड़ों रुपए आईटीआर से मांगे हैं। उसकी सूचना अधिकार में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है जो उच्चाधिकारियों की जालसाजी सिद्ध करती है।

ट्राई के संरक्षण में रु. 4 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट होती है जनता से

सफेदपोश डकैत है सभी सेल फोन कंपनियां

काल ड्रापिंग, रिंग, कालर टोन, झूठे विज्ञापनों से हर दिन रु. 1000 करोड़ की लूट

भारत में वर्तमान में दूरसंचार सेवा में भा. संचार निगम लि., एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, इस्सार, एयरसेल, विडियोकान, टाटा जैसी कं. राष्ट्र की 125 करोड़ जनता जिसके पास लगभग 98 करोड़ मोबाइल हैं, प्रतिदिन लगभग हर उपभोक्ता को रु. 10 प्रति सिम के हिसाब से न्यूनतम लूट ही रही हैं। अर्थात रु. 980 करोड़ से रु. 1000 करोड़ की लूट और वार्षिक औसत लूट रु. 4 लाख करोड़ की की जा रही हैं, लूटने के नाम पर निजी संयुक्त उपक्रम कं. से लेकर सरकारी भ्रष्ट शूकर, निकम्मा बनाम बीएसएनएल भी चूंकि सरकारी है, इनकी काल ड्रापिंग तरंग का अभाव, जो कि जनाबूझकर की जाती हैं ताकि उपभोक्ता परेशान होकर दूसरी कंपनी में चलाजाये और बीएसएनएल के अधिकारियों को महीना मिलता रहे, से लेकर रिलायंस स्मार्ट और रिम वायरलेस इन लोकल लूप, एयरटेल, टाटा, आइडिया, वोडाफोन, एस्सार, एयरसेल, वीडियोकॉन आदि सभी निजी क्षेत्र की कं. उसके उपभोक्ताओं से जबरदस्ती रिंग टोन, कॉलर टोन, संगीत, गाने, ज्योतिष, क्रिकेट, समाचारों, ब्रांडबैंड, इंटरनेट, एसएमएस, एमएमएस के नाम पर भी रु. 30-50 से लेकर सैकड़ों रु. का कटोत्रा काटकर वसूली कर रही हैं और इन हरामखोर जालसाज कं. से इस लूट और डकैती को पूछने वाला व रोकने वाला कोई नहीं है। ताजा समंकों के अनुसार 31 मार्च 2012 तक करीब देश में 98 करोड़ मोबाइलधारक थे, यदि इन गिद्ध मोबाइल सेवा प्रदाता कं. ने मात्र प्रति ग्राहक औसतन रु. 10 प्रतिदिन भी झूठे विज्ञापनों में काल दरें दिखाकर एसएमएस, रिंग कॉलर टोन, संगीत, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ज्योतिषसमाचार, क्रिकेट अपडेट आदि किसी भी तरीके से ग्राहकों से जबरदस्ती या उसकी मर्जी से भी लूटा तो प्रतिदिन रु. 980 करोड़ से लेकर रु. 1500 करोड़ प्रतिदिन की लूट अर्थात रु. 30000 करोड़ से रु. 50,000 करोड़ की और वार्षिक न्यूनतम रु. 4 लाख करोड़ रु. 6 लाख करोड़ की लूट की जा रही है। जबकि कमाई का ये आंकड़ा रु. 500 से रु. 700 लाख करोड़ का है। सबसे बड़े डकैतों में रिलायंस स्मार्ट, रिम और टाटा, निजी क्षेत्रों की कं. थी, जो पिछले 10 वर्षों से रिलायंस पिछले 6 वर्षों से टाटा जबकि पुराने दिग्गज खिलाड़ियों में एयरटेल और आइडिया भी हैं। ये इसी लूट के कारण रु. अरबों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बन गये, इस लूट में से इन कंपनियों ने मात्र रु. 1000 करोड़ भी महीने का टुकड़ा दिल्ली के संचार मंत्रालय के मुखेरे मंत्री सचिव से लेकर ट्राई और पूरे राष्ट्र में भ्रष्ट सूकर निकम्मा लि. के हर जिला अधिकारी जिनके आधारभूत संचार तंत्र पर सभी कंपनियों का संचार तंत्र चलता है, को भी बांटते हैं, ताकि ये बीएसएनएल के जिलाधिकारी उर्फ महाप्रबंधक प्रबंधकों से लेकर तकनीकी स्टॉफ उन मोबाइल कं. के लाभ के लिये व स्वयं की मोबाइल सेवा, फोन लाइनों, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, इंटरनेट, वीडियो कालिंग, डाटा ट्रांसफर जैसी अनेकों सेवाओं की निकृष्ट सेवायें, जानबूझकर तरंग दैर्ध्य की आवृत्तियों को कम ज्यादा कर, भार ज्यादा बढ़ने पर ठप्प करने, बार-बार संबंध विच्छेद करने आदि से उपभोक्ताओं को परेशान करने आदि का षडयंत्र करते रहते हैं। ताकि इनके भारतभर में फैले करोड़ों उपभोक्ता दूसरी कंपनियों की तरफ चले जायें। यही कारण था, कि इन जालसाजों ने नं. पोर्टबिलिटी सुविधा चालू करवाई ताकि ये जालसाजीपूर्ण तरीके से ग्राहकों को आकर्षित कर सबसे ज्यादा नुकसान बीएसएनएल को पहुंचा सके, दूसरी ओर इन नं. को आधार बनाकर अनेकों प्रकार से अन्य जालसाजियां आय पर करों, सेवाकर आदि की भी चोरी कर सकें।

रिलायंस और एयरटेल ने तो अनेकों सहयोगी कं. बनाकर अरबों रु. की कर चोरी और जालसाजी की घटनायें कभी से ही करते आ रहे हैं। एयरटेल ने टचटेल और टचटेल से फिर एयरटेल में हजारों करोड़ का चंदन बीएसएनएल को लगाया वरन आयकर और सेवाकर में भी अरबों के घोटाले चार्टर्ड बनाम करप्ट एकांउटेंटों के साथ मिलकर किये और कर रही हैं। पर टाई बनाम टेलिफ्रॉड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बैठे अधिकारी हर महीने अरबों रु. डकारकर एक तरफ जनता को हर महीने रु. 30,000 करोड़ से लेकर रु. 50,000 करोड़ की चोट पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी ओर लाखों करोड़ रु. प्रति वर्ष की चोट बीएसएनएल और आयकर व सेवाकर को दिलवा रहे हैं। इसी अरबों की डकैती डालने और लूटने के लिये दो विदेशी कं. एयरसेल कनाड़ा यूएस और वोडाफोन ब्रिटेन ने भी अपना जाल पूरे देश में फैला दिया है

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अपने बाप की जागीर समझते हैं सत्ता को, लोकतंत्र में सत्ताधीश

महाभ्रष्ट इकबाल अहमद को नवाजा मु.सु.आ. के पद से

जनता से करों में वसूल कर क्यों हिसाब नहीं देंगे, कानून बना दिया मजाक

भारत में यूपीए की प्रथम पारी में जनता का आक्रोश समाप्त करने और सरकार को जनता के प्रति समर्पित बताने के षड्यंत्र में एक ही कार्य अच्छा किया था, वह था सूचना का अधिकार अधि. 05 का लागू किया जाना, पर लागू किये जाने से पहले ही बनाने के समय ही पूर्ण षड्यंत्रों के साथ ही लागू किया गया था, लागू करते समय ही सबने यथार्थ में बचने की गलियां भी बना ली थी।

भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 55 वर्ष बाद सूचना का अधिकार लागू किया गया, उसकी धारा 4 में व्यवस्था की गई थी कि हर विभाग में क्या कार्य होता है, कौन-कौन लोग किस पद पर, किस वेतन के साथ कब से बैठे हैं, क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कितना धन का किस कार्य में व्यय हुआ आदि 17 बिंदुओं की जानकारियां डाली जानी चाहिये थीं, जिसके लिये रु. अरबों का खर्च किया गया, परन्तु 12 अक्टूबर 2005 से सन् 2012 का अक्टूबर आने वाला है अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तक के कार्यालयों की साइटों और उस पर डाली जाने वाली जानकारी तक का पता नहीं है। आखिर भारत का लोक निहायत ढीला और सत्ता का तंत्र बेहद गंदे शूकरों की फौज, जिन्हें भ्रष्टाचार की गहरी लूट की गंदगी में लोट लगाकर पैसा इकट्ठा कर विदेश भेजने की आदत है। फिर सत्ता में बैठा चाहे कांग्रेसी डकैत हो, बसपा की मायावती हो, सपा का मुलायम हो या भाजपा का रमन बैस, शिवराज या उनकी सरकारों का मंत्री से लेकर पार्षद अर्थात सत्ता किसी की भी हो, कोई भी बैठा हो लूटतंत्र का हिस्सा हैं, तो आकिर कैसे डालें जानकारियां, होगा सूचना का अधिकार, सत्ता में आते ही, चाहे वह केन्द्रीय हो, राज्यों की से लेकर नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं, जनपदों से लेकर ग्राम पंचायतों तक की हर सत्ताधीश को मालूम हो उसकी औकात 5 वर्ष की है। इसके साथ ही राज्यों से लेकर केन्द्र में बैठे धूर्त गिद्धों को उनके अपने ही मंत्री, सिपहसालार और सहयोगी कभी भी सत्ता पलट सकते हैं। इसलिये जब तक है जितना लूट सके तो लूट, अंत काल पछतायेगा, सत्ता जायेगी छूट। इसलिये सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ, जनता को जितना करों से लादकर नोंचा जा सके नोंचो और अपनी कमाई के लिये अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिये जनता को रोटी मिले न मिले, कभी मोबाइल बांटने के नाम, कभी गेहूं बांटने के नाम, सायकल बांटने के नाम हजारों-करोड़ डकार जाओ।

सत्ताधीश शूकरों यदि जनता से धन वसूला है, तो अगर तुम में थोड़ी सी गैरत बची हैं, तो उसका हिसाब तुम्हें देना ही चाहिये, सूचना का अधिकार कानून बना देने से अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती और फिर कितने ईमानदार हैं, क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने पूरे देश की राजधानियों में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोल केन्द्रीय क्षेत्रीय सूचना आयुक्त बैठाये, नहीं बैठाये क्योंकि हरामखोरों को डर है कि अपने कुकर्मों की धज्जियां न बिखर जायें, दूसरी ओर म.प्र. में ही देखें कि जब तक भाजपाई धूर्त विपक्ष में थे तब तो भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार चिल्लाते थे अब जब सत्ता में बैठे हैं। जर, जंगल, जमीन, जन को हर कदम लूटने खोदने में लगे हैं। सूचना के अधिकार के धूर्त, मक्कार, शूकरों की फौज ने पहले तो सात वर्ष में 1-2 वर्षों तक तो मात्र एक ही मुख्य सूचना आयुक्त जो महाभ्रष्ट था, विधि विभाग में सचिव रहकर सरकारों के भ्रष्टाचारों को बचाने का खेल रहा था उस सचिव पक्ष पाणि तिवारी को ही बैठाकर रखा जब उच्च न्यायालय से जनता ने आदेश करवाया, तब भी मात्र पूर्व के मुख्य भ्रष्ट जालसाज अधिकारियों इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा पुलिस का से.नि. डीजीपी दिनेश जुगरान को बैठा दिया, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिद्ध हुआ सू.आ. इकबाल अहमद, इसके पी.ए. सक्सेना की रु. 5 से 10 हजार की मुट्ठी गर्म कर दो, ठोस अपील होने के बाद भी ये महाभ्रष्ट हजारों अपीलों को निरस्त कर देता है, स्वाभाविक आवेदक को क्षतिपूर्ति और अनावेदक पर रु. 250/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाना तो बहुत दूर की बात है, यदि श्री अजमेरा की जो ये हर वर्ष 25-50 अपीलें, 07, 08, 09, 10, 11, 12 में निरस्त कर चुका है। इस पर 120 बी आपराधिक षड्यंत्र कर बचाना, धारा 179 लोक प्राधिकारी को जो कि उत्तर देने के लिये जिम्मेदार है, धारा 217 जिसमें लोक प्राधिकारी जो कि कानूनों को नहीं मानकर मनमानी कर रहा है और अनावेदकों को दंड से बचा रहा है, धारा 218 जिसमें लोक प्राधिकारी जानबूझकर त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य कर अनावेदकों को दंड से बचा रहा है, में भी प्रकरण लगाये जा सकते हैं, पर भारतीय न्यायालयों में समय और धन के आत्यधिक व्यय के कारण प्रकरण नहीं लगाये जा सक रहे हैं। अन्यथा सूचना अधि. के अतिरिक्त भी सत्र व जिला न्यायालय में प्रकरण लगाया जा सकता है। निःसंदेह यह भी सच है कि ऊपरी स्तर पर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वल्लभ भवन का सचिवालय हो या लोकसभा का सचिवालय सबका चोली-दामन का साथ हैं। इसलिये केंद्रीय सूचना कार्यालय से लेकर राज्यों के सूचना आयोगों के कार्यालय तक पूरे देश में हर पद पर चुन-चुन कर भ्रष्टों को बैठाया गया है, आखिर केन्द्र में बैठाये गये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति केन्द्र सरकार के ही प्रधानमंत्री कार्यालय से तो राज्यों में राज्य के मुख्य भ्रष्ट मंत्री कार्यालय से तो आखिर श्वान जिस की रोटी खायेगा उसी को देखकर तो दुम हिलायेगा, जनता के आवेदकों को देखकर तो भौंकना ही है, ताकि डरकर आवेदक भग जाये, फिर आवेदन ही नहीं लगायेगा, परन्तु ये सत्ता के शेर यह नहीं जानते कि जंगल का असली शेर भी नैले श्वानों को देखकर डरकर भाग जाता है।

जब से म.प्र. का सूचना कार्यालय शुरु हुआ है, तब से लेकर अभी तक आयोग की कार्यवाही ही पूरी अवैध तरीके से चलाई जा रही है, सूचना आयोग एक तो डेढ़ से दो वर्ष तक बाद तक सुनवाई करता है और आवेदक को सीधे ही पक्ष रखने को कहता है, जबकि जैसे अनावेदक को अपील भेजकर जवाब मांगता है, क्या अभी तक आवेदक को अनावेदक के जवाब की प्रति आवेदक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत भेजता है। 7 वर्ष पूर्व से शुरु हुए आयोग में बैठे धूर्तों की कैसी कार्यवाही और अपील सुनने की प्रक्रिया हैं कि आवेदक को बिना बताये ही कि अनावेदक ने क्या जवाब भेजा है सीधे ही आवेदक को अपील में सुनवाई हेतु सीधे ही सामने बैठाकर वो भ्रष्ट, जालसाज अब मुख्य सूचना आयुक्त बनाकर बैठाया गया डांटने, फटकारने से लेकर अपनी अपील निरस्त करने की कार्यवाही कर अनावेदक से वसूली कर उसे साफ बचा लेता है, स्वाभाविक है, जब अपील ही निरस्त कर दी जाती हैं, तो अधि. की धारा 19 (8) सी में क्षतिपूर्ति, आवेदक की हानि के लिये और धारा 19 (8)बी में अनावेदक पर आर्थिक रु. 250 प्रति दिन का दंड तो दूर की कोड़ी है, दूसरी ओर लेन-देन में सौदा नहीं भी पटा तो केवल धारा 7 (6) के अंतर्गत मुफ्त में चाही गई जानकारी का आदेश अगर कर भी दिया गया तो भी भ्रष्ट, मक्कार, जालसाज अनावेदक ने जानकारी दी भी या नहीं, आयोग कभी अनावेदक से ये पूछने का और आदेश पर क्या कार्यवाही की गई भी या नहीं ये पूछने की कोशिश भी नहीं करता।

सूचना अधिकार अधि.05 के लगने के बाद से ही जो कि बहुराष्ट्रीय कं. के दबाव में लगाया गया ताकि उन बहुराष्ट्रीय कं. को भारत में व्यापार में, सरकारी कार्यों में, उनके हितों को साधने में परेशानी न हो, 4-5 वर्ष के भारी दबाव के बाद केन्द्र के धूर्त प्रधानमंत्री मनमोहन ने लगा तो दिया, परन्तु 12 अक्टू.05 से ही न केवल राज्य सरकारों ने वरन् केन्द्र सरकार ने भी बलात्कार करने, संशोधन करने और शुल्क बढ़ाने, सीमित जानकारी मांगने पर विवश करने के प्रयास लगातार किये जाते रहे हैं। कानून में जबकि स्पष्ट लिखा है कि संशोधन की अवधि दो वर्ष होगी इसके विपरीत म.प्र. में स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार को दूर करने के घड़ियाली आंसू बहाने वाले भ्रष्ट मु.मं. शिवराज ने रु. 2/- से शुल्क को सन् 2008 के राजपत्र में जालसाजी पूर्ण तरीके से रु. 10 प्रति पेज कर दिया, जबकि वह केवल गैर कानूनी था दूसरी ओर 50 पै. की फोटोकापी के रु. 2/- अर्थात 4 गुना शुल्क वसूलना भी केन्द्र सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा ही था, ताकि ये जनता का धन हजम भी करते रहे और कोई इनसे पूछे भी नहीं कि ये आखिर वे जनता पर बेहताशा कर थोपकर धन का क्या सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता इनके बाप की जागीर है, और जनता इनकी रखैल, ताकि जब जैसा चाहे ये नोचे-खसोटें और कोई इनसे पूछताछ भी न करें।

सफेदपोश डकैत है सभी सेल फोन कंपनियां

पृष्ठ 4 का शेष

जिसके माध्यम से तो अब जासूसी, भारतीय व्यवसाय, जनता के धर्मों, परंपराओं से लेकर जनता की वर्तमान आवश्यकताओं, शौक आदि पर भी निगरानी और जासूसी के साथ डाटा भी चुपचाप इकट्ठा करती रहेंगी, जो बहुराष्ट्रीय कं. को अपने पैर जमाने और देशी व्यापार व अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के काम भी आयेगा और ट्राई में बैठे टेलीफ्रॉड रेग्युलेटरी के सदस्य, महीने मिलने पर टुकुर चबाते चुपचाप बैठेंगे।

इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है कि सभी दूरसंचार कं. अपना डाटा टेली मार्केटिंग कं. को बेचकर भी अरबों रु. कमा रहा हैं। अब इंग्लैंड अमेरिका से भी आम उपभोक्ता को करोड़ों रु. की लॉटरी लगने, इंडोनेशिया, थाईलैंड से वहां बैठी वेश्याओं से बात करने, रात गुजारने के भी आमंत्रण, भारतीय व्यापार कं. के साथ मिलने लगे हैं। भारतीय दूरसंचार कं. युवा महिलाओं को वेश्यावृत्ति के जाल में धकेलने, युवा छात्रों और पुरुषों को दोस्ती के चलते वेश्याओं के जाल में फंसाने के कारोबार में, पुरुषों को लिंग लंबा करने, स्त्रियों की योनी और वक्षस्थल कड़क बनाने के आमंत्रण दवा विक्रेताओं, डॉक्टरों से सीधे ही मोबाइल पर भेज रहे हैं। आखिर ट्राई के गिद्धों ने क्या किया सिवाय वसूली करने के। सरकार ने आखिर इस संस्था को क्या केवल नोंचने, खाने और कमाने के लिये बैठाया है, क्यों आखिर ट्राई के शूकरों की फौज इसको नहीं रोक रही और जनता को लुटवाने के लिये इन जालसाजों को छुट्टे सांड की तरह छोड़ रखा है, क्यों ऐसे काटों और लघु संदेशों पर ट्राई का नियंत्रण और कानून नहीं है। क्यों बैठाया गया है, दूरसंचार तकनीकी बढ़ने पर, शासकीय कानून क्या है जो इन जालसाजों की लूट और डकैती रोक सके और कंपनियों के संचालकों को 2-5 वर्ष के लिये अंदर कर सके, आखिर ये कंपनियां क्या अपने ग्राहकों को अपने बाप की जागीर समझती है जो उनका डाटा नं. किसी को भी उपलब्ध करवाकर जालसाजों को लूटने के लिये खुला छोड़ देती हैं। पूरे राष्ट्र में इन मोबाइलों के कारण वेश्यावृत्ति की बाढ़ आ गई हैं, यौन स्वच्छंदता ने राष्ट्र की युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया है, इसके उदाहरण मानसिक चिकित्सकों से लेकर निजी और सरकारी चिकित्सालयों में बढ़ती युवाओं की भीड़ से लगाया जा सकता हैं पर केन्द्र सरकार में बैठे धूर्तों को अपनी यौनचारिता और कमाई में बढ़ोत्री ही हुई है। इसलिए उन्हें इन सबसे क्या लेना देना।

ट्राई की साइट पर जाओ तो वहां शिकायत भेजने के लिये कोई भी ईमेल हरामखोरों ने जानबूझ नहीं दिया क्योंकि यदि 1% लोगों ने भी ईमेल भेजे तो प्रतिदिन 98 लाख ईमेल पहुंचेगे। मात्र मोबाइल पर हरामखोरों ने अनावश्यक एसएमएस रोकने, उनकी शिकायत करने के लिये 1303 का नं. भर दिया है, पर अनावश्यक कटोत्रा करने, जबरदस्ती रिंगटोन, कालर टोन, सेवायें थोपकर वसूली करने, कालरेट में ज्यादा वसूली करने, बैलेंस उड़ा देने, सेवायें थोपने के नाम पर अनचाहे वसूली करने आदि सैकड़ों प्रकार की लूट और शिकायत करने की जालसाजी पूर्ण तरीके से लॉटरी लगने और पैसा भेजने, टीवी पर विज्ञापन दिखाकर इनाम देने, बदले में पैसा भेजने पर, रेती की पुड़िया भेजने जिसके विज्ञापन पर सभी बड़े समाचार पत्रों में यथा भास्कर, राज एक्सप्रेस, पत्रिका आदि में छापे जा रहे हैं कि शिकायत करने जिसमें बच्चे, महिलायें और ग्रामीण ज्यादा लपेटे में आकर हजारों लाखों रु. गंवाते हैं को रोकने आदि की कोई व्यवस्था ट्राई की साइटों पर कहीं भी जानबूझकर नहीं की गई क्योंकि 98 करोड़ उपभोक्ताओं में से सभी को इन डकैतों से शिकायत है, 98 करोड़ मोबाइल और 20 करोड़ सभी कंपनियों के लैंडलाइन ग्राहकों को शिकायत, जिसे सरकारी बीएसएनएल से लेकर अन्य सभी निजी कं. नहीं सुनती है और उपभोक्ता लूटता रहता है। उपभोक्ता फोरम, न्यायालय भी न केवल समय और पैसे की बर्बादी भी करवाते हैं और सालों चक्कर कटवाते हैं वो अलग से, फिर ये लोक अदालतों का नाटक खेलकर भी लूटते तो जनता को ही हैं। अब आवश्यकता है कि ट्राई को ऐसी शिकायतें रोकने त्वरित कार्यवाही करने, कं. को भारी अर्थदंड देने जनता को राहत पहुंचाने के लिये अपने कार्यालय पूरे देश के हर जिले में खोलकर लाखों करोड़ की इस लूट को रोकें। अन्यथा लूटतंत्र में वर्षों से लूट तो चल ही रही है। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सब भ्रष्टों के पाले श्वान हैं।

बजाज के स्तरहीन स्कूटर और बाइक्स ने चालकों को किया परेशान

(पृष्ठ 3 का शेष)

जिससे एक्सीलेटर उल्टा चलने लगता है, फिर इसके ब्रेक प्लेट के बारे में मिस्त्रियों ने बताया कभी भी पूरे फेल हो जाते हैं और अंदर ही टूट जाती है जिससे दुर्घटनायें हो जाती हैं। चौथा चेन के गियर्स और पूरी चेन न केवल जल्दी गिली हो जाती है वरन स्लिप भी मारती है। 20-25 हजार कि.मी. गाड़ी चलने में ही इंजिन बैठ जाता है, मोल्डेड पटियों की परेशानियां मात्र इसलिये खड़ी की गई ताकि मोटी कमाई की जा सके और पहिये में खराबी आने पर पूरा मोल्डेड रिम डालना पड़े, बेशक ये बत्तमीजी नोंच खसोट की मानसिकता से हर वाहन निर्माता कं. यथा हीरो होंडा, हीरो सुजुकी, बुलेट, टीव्हीएस सभी ने दो पहिया गाड़ियां बनाना ही बंद कर दी जो वाहन चालक के लिये ज्यादा सुरक्षित थी।

बजाज की डिस्कवर में अनोकों बदइंजामियां डिस्कवर करके डाली हैं। जैसे बरसाती मौसम में इसकी गाड़ी लोड नहीं लेती और न केवल धीमी और चलने में भारी ताकत मांगती है, ये बदइंतजामी पूर्ण विशेषता सीटी 100, प्लेटिना में नहीं पाई जाती व अन्य गाड़ियों में भी नहीं होती, हीरो होंडा में इंजन भर दमदार होता है, परन्तु इनमें सबसे बड़ी कमी गाड़ी की लंबाई भारतीयों के हिसाब से नहीं वरन जापानी ठिगने पिट्ठों के हिसाब से रखी गई है, हीरो होंडा और होंडा में ये हरामखोर अपनी महानता और श्रेष्ठता दिखाने के लिये इस हाथ पैसा उस हाथ माल या वाहन न देने के कारण ही देश में बजाज अपने दो पहिया वाहन प्लेटिना, डिस्कवर, पल्सर व अन्य वाहन बेचता रहा है, उसकी सीटी100 भले ही औसत नहीं देती थीं, पर मिस्त्रियों की शक्ल ताकने का मौका भी कम ही देती थी। पर इन हरामखोरों ने पुनः वो बदइंतजामियां अपने सारे वाहनों में भर दी हैं। यदि जालसाज नहीं सुधरे तो साल दो साल में प्लांट बंद करना पड़ेगा, होंडा की गाड़ियां महंगी और जापानियों के हिसाब से बनाई गई हैं। बजाज भी छोटी करने से बेडोल हो चुकी हैं। कं. शीघ्र सुधर जाये तो बेहतर होगा।

साप्ताहिक समय माया

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संरक्षण में चल रहा तांडव

अधिकांश राशन सहकारी संस्थायें अवैध, लगी हैं लूटमार में

सारे खाद्य अधिकारी लगे हैं महीना वसूली, राशन दुकानों मिट्टी तेल, हॉकरों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों को दे रखी है लूट की पूरी छूट

म.प्र. में विश्व में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिकता है, इसकी पुष्टि तो अनेकों समाचार पत्रों ने तुलनात्मक अध्ययन छाप कर तो पहले ही कर दी है। इसके साथ ही रु. 74/- प्रति लीटर का पेट्रोल वास्तविकता में रु. 120 से रु. 150 प्रति लीटर तक उपभोक्ताओं को पड़ रहा है। क्योंकि म.प्र. में 58 आवंटन का पेट्रोल मात्र 38-40 आवंटन का होता है, उसमें भी खुलकर 20 से 80% तक मिट्टी के तेल, साल्वेंट, नेफ्था तक की मिलावट और ऊपर से 10% से लेकर 50% तक पेट्रोल के नापने में चोरी कर ली जाती है वो अलग से, जिसका करिश्मा मूसाखेड़ी के पुलिस पेट्रोल पंप पर हुआ। जिसमें कार के 40 ली. के टैंक में 55 ली. पेट्रोल भर दिया गया, ये नापतौल विभाग का खेल हैं।

विभाग का कहना है कि पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिये विभाग ने अनेकों नमूने लिये और उसमें 25% तक मिट्टी का तेल मिलाकर प्रदेश की एकमात्र तेल कं. की प्रयोगशाला में भेजे गये जो सभी पास कर दिये गये, अर्थात प्रदेश सरकार के पास पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने के लिये कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। इसलिये ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नमूने लेने का काम लगभग औपचारिक कर दिया है। पेट्रोल पंपों को मिलावट की खुली छूट दे रखी हैं। ताकि रु. 20-25 हजार स्तर के हिसाब से वसूली तो मिलती रहे, जनता लूटती रहे, जनता तो कमाती ही लूटाने के लिये ही है। स्वाभाविक है कि दूसरे इनके पास एक क्षेत्र है, जन वितरण प्रणाली जिसमें उचित मूल्य की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे, ऊपर वालों को, अन्त्योदय वालों को गेहूं, चावल, शक्कर,मिट्टी का तेल का वितरण उचित मूल्य पर करवाते हैं। जिसकी सत्यता का प्राथमिक स्तर पर देखे तो ये सभी राशन दुकानें सहकारिता के अंतर्गत चलाई जाती हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, तो मात्र इंदौर जिले की जानकारी के स्थान पर इंदौर शहर की दी गई, जिसमें 257 दुकानें थीं, जबकि महू, सांवेर, देपालपुर की जानकारी ही नहीं दी गई, कुल मिलाकर लगभग 480 राशन दुकानें हैं। जिनमें 99% में वर्षों से चुनाव ही नहीं हुए हैं। जब जिम्मेदारों से पूछा गया कि इनकी सहकारी समितियों में कब से चुनाव नहीं हुये हैं तो जिला खाद्य अधिकारी और सहा. खाद्य आपूर्ति अधिकारियों का रटा-रटाया सा जवाब था कि ये कार्य सहकारिता विभाग का है, उससे पूछो अर्थात इन हरामखोरों का एक ही काम है, कि तुम कुछ भी करो, इनको बस महीना पहुंचाते रहो, इन सब राशन दुकानों का यथार्थ यह है कि सहकारी संस्था तो केवल दिखाने की हैं, सारी संस्थायें एकल व्यवसाय की तरह गली-मोहल्ले के गुंडे-बदमाशों, नेताओं द्वारा चलाई जा रही हैं। यह हाल इंदौर का ही नहीं प्रदेश के 50 जिलों में चल रही लगभग 25000 से ज्यादा राशन का गेहूं, चावल, मिट्टी तेल, शक्कर आदि की आपूर्ति राज्य के गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर वालों को उचित मूल्य के नाम पर सरकारी योजना का रु. 3 प्रति किलो का गेहूं हरामखोर, जालसाज रु. 3 से रु. 5/- प्रति किलो हितग्राहियों का और बच जाने पर गेहूं खरीदी में रु. 1280/- प्रति क्विंटल या मिल वालों को रु. 15 प्रति किलो तक में बेचकर ही मोटी कमाई कर संबंधित जिला सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, जिला अधिकारी को महीना तक पहुंचाकर सबका मुंह बंद रखते हैं। यही हाल मिट्टी के तेल का है रु. 9/- से 15/- प्रति लीटर का तेल रु. 30 से 40/- प्रति लीटर में खुले बाजार में बेचा जाता हैं, ये धूर्त अधिकारी और निरीक्षकों द्वारा प्रति सप्ताह मिलने वाले 200 ली. के कोटे में से भी रु. 200/- से रु. 500/- प्रति महीना वसूल लेते हैं। स्वाभाविक है अधिकांश हितग्राहियों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता, जो कि लगभग 1200 से ज्यादा हॉकरों का जो पूरे इंदौर महानगर में फैला है, रु. 500 प्रति माह या हर 200 ली. के कोटे पर रु. 200 देकर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने की खुली छूट मिल जाती है, जिसमें से छूटभैय्ये नेता पार्षद भी वसूली कर लेते हैं। वितरण और डीलरों के अधिकांश के पेट्रोल पंप हैं तो सीधे ही टैंकर के टैंकर पेट्रोल में मिलाकर उसे रु. 74/- प्रति लीटर में बेच देते हैं। वाहन चालकों को, इस प्रकार एक टैंकर केरोसीन से ये 12 लाख रुपये, जो 20000 ली. का होता है, ये वितरक और डीलर कमाकर रु. 20,000 तक का भुगतान खाद्य नियंत्रक को कर सबका मुंह बंद कर देते हैं। जिसका पैसा मंत्री सचिव तक मासिक तौर पर भिजवाया जाता हैं। स्वाभाविक है, सबके मुंह के आकार का टुकड़ा जनता को लूटकर मिल रहा है, तो सहा. खाद्य अधि. न जिला अधिकारी से लेकर मंत्री तक सारे हरामखोरों की श्वान फौज चुप रहेगी, जब वसूली मिल रही है तो काहे के पेट्रोल पंपों से डीजल, पेट्रोल और गैस के नमूने लिये जायेंगे और क्यों लिये जायेंगे, इंदौर में कलेक्टर सुलेमान के समय 'समय माया' के इन तथ्यों को छापने पर पेट्रोल पंपों पर पारदर्शी ट्यूब लगाने की पहल की गई थी, इस संबंध में जब खाद्य नियंत्रक से बात की गई तो गुर्राकर बोले ये मेरा काम नहीं कंपनियां जानें, सच भी है, इनका काम केवल दोनों हाथ से वसूली कर एक हाथ से अपने आकाओं तक पहुंचाना हैं, जबकि सच यह भी हैं कि पूरा 15-20 का पाइप पारदर्शी न भी हो, 1 इंच से 6 तक का कांच का पाइप स्टील के नोजल के पास लगाने के लिये जालसाज तेल कं. को लगाने के लिये विवश किया जा सकता है ताकि पेट्रोल के रंग से गुणवत्ता का पता लग सके और ग्राहकों को लुटने से बचाने के साथ ही उनके वाहनों को खराब होने और प्रदूषण से बचाया जा सके, इसके विपरीत मालयान, पुलिस पेट्रोल पंप बाणगंगा, महेशगार्ड लाइन मूसाखेड़ी, हवाई अड्डा मार्ग, गंदा तालाब आरबी फिलिंग स्टेशन जैसे अनेकों पेट्रोल पंपों पर देखा गया कि भीड़ के वक्त उपभोक्ताओं को परेशान करने की नीयत से एक दो प्वाइंट बंद रखे जाते हैं, ताकि भीड़ में न केवल कम नाप का पेट्रोल लिया जाये और मिलावटी बेचा जाये इसके लिये सीधा टंकी में पाइप घुसेड़ कर पेट्रोल भरा जाये। 90% पेट्रोल पंपों पर भौतिक नाप से पेट्रोल नहीं दिया जाता। अनेकों बार खाद्य नियंत्रक शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिये पूर्व जिलाधीश सुलेमान टैंकर खाली करते समय उसकी सील और गुणवत्ता देखने के लिये निरीक्षकों और सहायक खाद्य अधिकारियों की टैंकर खाली करते समय ड्यूटी लगाई जाती थी, पर उसके जाते ही सब पुराने ढर्रे पर आ गया और सब महीना वसूली पर ध्यान लग गया, नगर और तहसीलों को मिलाकर सभी कंपनियों के लगभग दो सौ से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर मिलावट की और कम नापने की पूरी छूट हैं, नापतौल निरीक्षकों को भी रु. 10,000 प्रति माह की बंदी बंधी है, तो स्वाभाविक है कि उन्हें भी हरामखोरी का दाड़ में खून लग चुका है, तो कैसे जांच करने जायें, फिर न केवल सहा. खाद्य अधिकारी जैसे अश्विनी नायक सेंगर, मनोरंजन दुबे और अनेकों वर्षों से कुंडली मारे बैठे है। इसलिये ही है कि सबको राशन दुकानों, हॉकर जो मिट्टी का तेल बांटते हैं, गैस एजेंसियों, पेट्रोल डीजल गैस पंपों से लेकर अनेकों अन्य स्त्रोतों से मोटा महीना मिलता है। अश्विनी नायक को न केवल 15 वर्षों से ज्यादा इंदौर में हो गये वरन उसने पत्नी के नाम से महू और राजेन्द्र नगर में गैस एजेंसियां भी चलाता है। वही हाल नापतौल निरीक्षकों का भी हैं कि पाटनकर जैसे अनेकों वर्षों से हरामखोरी और लूटो और लुटाओं के खेत के दम पर जमे हैं। निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव 15 से ज्यादा वर्षों से जमे रहकर 1 वर्ष के लिये देवास गये थे लौटकर इंदौर में जम गये हैं। यही हाल उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, सागर, ग्वालियर का भी हैं, मंत्री पारस जैन को महीना पहुंचता रहे, क्या करना है उस धूर्त को, उस हरामखोर को उसकी औकात मालूम है यदि अगला चुनाव हार गये या पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो कोई पलटकर नमस्कार भी नहीं करेगा। सूचना के अधिकार में आवेदन दिया तो उसके जवाब में ही अपनी हरामखोरी और जालसाजी का परिचय दिया गया, बिन्दु क्र. 4 में पूछा गया कि विभागीय नियमों के उल्लंघन में आपने क्या कार्यवाही की गई, 1 अप्रैल से 30/06/11, 01.07.11 से 30/9/11, स. 1/10/11 से 31/12/11, द. 1/1/12 से 31/3/12 और ई. 1/4/12 से 15/5/12 तक। इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद सीधे रु. 11000/- मांगे गये जबकि बिन्दु बार और समयावधिनुसार शुल्क का वितरण मांगा गया था, अपील की गई तो यह तो ज्ञात ही था जिलाधीश आकाश त्रिपाठी पूर्व का भ्रष्ट निगमायुक्त ही हैं, बिना पढ़े ही उन्हें थोड़ी सी नसीहत देकर चलता कर देगा किया भी वहीं, अवलोकन कर लो और जो चाहिये ले लो पर जो इन हरामखोरों ने जालसाजियां की और कर रहे हैं। उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, आखिर महीना तो इसी लूट में से मिलेगा कैसे कोई टिप्पणी की जा सकती है। जहां तक जनता के लूटने का सवाल है, तो वह तो बैठा ही लूटने के लिए हैं।

शिवराजसिंह सर्वोच्च....

पेज 1 का शेष

उनमें आग लगा दी जाती है। फिर भूमाफियाओं को सौंपकर वहां कालोनियां काटी जाती हैं। उद्योग खड़े किये जाते हैं। बदले में मोटा कमीशन हजम करने के साथ ही भविष्य में कमाई की व्यवस्था स्थायी की जाती हैं। जिस बिजली पानी के दम पर सत्ता हथियाई जाती हैं, वो उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को तो दी जाती है और जनता को अंधेरे में रखकर पानी के स्थान पर आंसू बहा कर पानी एकत्रित करने के लिये छोड़ दिया जाता है। जिन सड़कों से चलकर नेता जी वोट मांगने जनता के घर-घर जाकर मुहर लगाने की याचना करते हैं और जनता जिन सड़कों से नेता जी को वोट देने जाती है। बाद में वे ही सड़कें सत्ताधीश अपने पट्टों को सौंपकर बीओटी से वसूली करने लगते हैं। फिर जिन्होंने नेता जी को सत्ता का ताज पहनाने के लिये नोट और वोट दिये होते हैं। वो ही स्वर्ण हिन्दू, उनके खासे दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो उनका हक देने की तो दूर उनके हक छीनने के लिये कानून बना लेते हैं और उन्हें खुश करने का पुरजोर प्रयास करते हैं। ताकि वो 10-20% वोट भविष्य में इनकी झोली में और आ जायें जो इन्हें कल और आज अपना घुर शत्रु समझते हैं।

सत्ताधीश सत्ता संभालते ही सारी व्यवस्थाओं को अपनी रखैल की तरह उपयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर हर सरकारी विभाग और उसकी संपत्तियां, यही कारण है एक तरफ भू माफियाओं को खुली छूट देकर चारों तरफ कांक्रीट जंगल खड़े करवाये जा रहे हैं। इन कांक्रीट जंगलों में अनेकों आदिवासियों, हरिजन और पिछड़ा वर्ग की जमीनों को भी हड़पा गया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में औद्योगीकरण के नाम पर आदिवासियों, हरिजनों, पिछड़ा वर्ग की न केवल कृषि भूमि के साथ गांवों के गांव खाली करवाये जाकर गांवों की पंचायतों की सीमाओं के शास. भूमि के जल, जंगल, जमीनों को खनन भूमाफियाओं, सड़क ठेकेदारों, निर्माण ठेकेदारों को वैध-अवैध रूप काट, खोदकर नोंचा जा रहा है। जिसका तात्कालिक उदाहरण है झाबुआ जिले में मैंगनीज माफिया सुधीर शर्मा की अनुमति 10 से 100 गुना ज्यादा खुदाई और कटाई करके हजम किया जा रहा है। तब आदिवासियों, हरिजनों के हितों का ख्याल क्यों नहीं आता, तब तो पूरे प्रदेश की संपत्ति चाहे फिर वह सरकारी, नजूल, ग्राम पंचायत के साथ ही आदिवासियों आदि किसी की भी आराम से मिल जाये तो ठीक अन्यथा पुलिस, गुंडों, धन देकर कैसे भी हो छीनने-हड़पने और औने-पौने से लेकर हजारों गुना तक ऊंची बेची जाती हैं। जबकि निजी या सरकारी तौर पर आदिवासियों की जमीन की बिक्री की अनुमति के साथ उसको वैकल्पिक जमीन भी दी जानी चाहिये। पर 90% आदिवासियों को जमीन औने-पौने में डरा धमकाने से लेकर आगजनी करने से भी बाज नहीं आते। सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर ऐसी सभी जानकारी देने से न केवल बचते हैं। जो कि न केवल उनका अहित करें वरन सत्ताधीशों पर भी सीधी आंच आये, जबकि पूरे प्रदेश में सभी प्रशासनिक जो जिलों की सत्ता में बैठे हैं। खुले में आदिवासी कल्याण के धन को न केवल हजम कर रहे हैं। वरन उनके नाम पर स्वयं भुटा कर बाइपास तक करवा रहे हैं। जब आदिवासी हित कहां चला जाता है। तब तो सत्ताधीशों का मद सिर चढ़े अपने मुंह मिट्ठू मियां बन झूठी तारीफों के यशगान सरकारी 90 प्रतिशत सवर्णों से वसूले गए आयकर विक्रयकर कस्टम एक्साईज सेवा करों की लाखों करोड़ की धन राशि से मीडिया के धूर्तों को खुश करने के लिए पूरे देश में अरबों रुपए के विज्ञापन दृश्य और सृव्य प्रचार माध्यमों पर खर्च किये जाते हैं। अपने नोट व वोट के लिए ही मात्र हरिजन आदिवासी प्रेम उमड़ता है। तभी हरामखोर गिद्धों की फौज जिनकों 30 वर्षों तक नोट और वोटों से इस मुकाम तक पहुंचे उनके हकों को भी संविधान के समानता के अधिकार की धज्जियां बिखेरते हुए सामान्य वर्ग को न केवल वरिष्ठता प्रतिभा संपन्न मेहनतकश ईमानदार कर्मचारियों व अधिकारियों, डॉक्टर, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों आदि को एक ही पद पर उनसे कनिष्ठों जिनकी सेवाएं सवर्ण वरिष्ठों की सेवाओं से आधी भी नहीं होती उन्हें मात्र बुखेरे गंदे नीच राजनीतिज्ञ अपनी रोटियां और महानता सिद्ध करने के लिए जबकि वे जानते हैं कि वे न केवल कनिष्ठ हैं कृपांकों की कृपा से पास होकर यहां आए हैं। उनके निर्णय भ्रष्टाचार और न केवल गुणवत्ताहीन जनधन की बर्बादी पूर्ण कार्यों से न केवल विभाग की छवि और जनधन की भी हानि हो रही है। पर इससे धुर्त मक्कार राजनीतिज्ञों को क्या मतलब है। इन्हें तो पांच वर्ष में जितने लूट सके लूट लें बेशक हरिजन आदिवासी वर्ग के कर्मचारी व अधिकारी भी इन धुर्त राजनीतिज्ञों की तन मन धन से ज्यादा सेवा चाकरी करते हैं। मप्र लोक निर्माण विभाग के इंदौर संभाग दो के कार्यपालन यंत्री बागोले स्वयं कहते हैं कि नियुक्ति में आरक्षण का लाभ ही सरकार को देना चाहिए। पदोन्नतियों में आरक्षण न केवल गलत है बल्कि राष्ट्रहित में भी घातक है। अकेले मप्र जैसे जलसंसाधन विभाग में इंजीनियर मुकुल जैन 30 वर्ष से एसडीओ है जबकि उनकी 11वीं बीई एमटेक स्ट्रक्लचरल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की मास्टर डिग्री है। इसे तीस वर्ष बाद प्रमुख अभियंता होना चाहिए था इसका लाभ देश प्रदेश को मिलता परंतु आज एसडीओ है ऐसे ही लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी में एसडीओ बर्वे एमटेक हैं। 30-35 वर्ष के बाद भी एसडीओ हैं। इन धुर्तों की बला से प्रतिभा शिक्षा वरिष्ठता कुछ भी नहीं केवल नोट और वोट चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान को स्वर्णों की पदोन्नतियों से मतलब नहीं। संविधान किसी भी राष्ट्र की आचार संहिता होती है। जो एक बार लिख गया वो पूरे राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करने से लेकर राष्ट्रीयता को संचालन का कार्य करती है। जिसमें संशोधन नहीं किये जाते पर दुनिया के किसी भी संविधान में अभी तक इतने संशोधन नहीं किये गये जितने की हमारे राष्ट्र के संविधान में। 21 अगस्त को कांग्रेसी अंग्रेजों की अवैध औलादों ने पुनः अपने स्वास्थ्य के लिए संविधान संशोधन के लिए सर्वदलिय बैठक इसलिए बुलाई थी कि संविधान संशोधन कर नागरिकों के मूल भूत समानता के अधिकारों का हनन कर सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों में आरक्षण देकर अपनी मोटी लूट और कमाई की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि केंद्र में सत्ताधीश कांग्रेसी और यूपी सरकार और मप्र में भाजपा की सरकार व अन्य सभी सरकारें, बहुराष्ट्रीय कं को सड़कें, बिजली पानी दूरसंचार, यातायात, परिवहन शिक्षा, नागरिक आपूर्ति रक्तदान प्राकृतिक संसाधन यथा नदियां, नहरें, विद्युत उत्पादन, कोयला सब सौंपकर मोटा कमीशन हजम करते रहे, शासकीय अधिकारी कर्मचारी ने केवल इसके विरुद्ध आवास न उठाए। तुरंत सवर्ण वर्ग ज्यादा बुद्धिमानी, नियम कानून की बात कर इन गिद्दों की लूट खसोट में जो व्यवधान पैदा करता है, और बहुराष्ट्रीय कं. की बत्तमीजियों और जालसाजियों में बाधक बनता है, वह आरक्षित वर्ग केवल यस सर, ठीक है सर हो जाएगा सर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हो जाएगा कर रहा है। जिस भाजपा को पूरे देश में सवर्णों से नोट वोट सपोर्ट दिलवाने के लिए रा. स्व. सेवक संघ ने जिस पितृ पुरुष की भूमिका निभाई, स्वदेशी आंदोलन चलाया, ये भाजपाई अपने उस पितृ संगठन पर ही वर्षों से बात कर रहे हैं। जिसके कारण रा. स्व.संघ को इंदौर में भाजपा का कार्यालय तक फोड़ना पड़ा हो, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मु. मं. शिवराजसिंह चौहान जो शक से बड़ा भोलू लगता है, पर भोलू कितना भोलू है कि पीथमपुर, बेटमा व आजू बाजू के 50 से ज्यादा आदिवासियों और हरिजनों की कृषि भूमि को बलात छीन कर बहुराष्ट्रीय कं. को बेच रहा है, आदिवासियों, हरिजनों के नाम से हजारों करोड़ का धन राज्य में, और लाखों करोड़ का धन कौन और क्यों हड़प रहे हैं। क्यों 65 वर्षों में उनका समुचित विकास नहीं कर पाए। जब ये हरामखोर रा. स्व. संघ के सगे नहीं हुए तो फिर सवर्णों के नोट वोट लेकर भी सगे कैसे हो सकते हैं। भले ही वो भीख नहीं मांग रहे हों अपने हक की बात कर रहे हों। कैसा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जो सत्ता में बैठा है। स्वाभिमान है शिवराज मुख्यमंत्री ज्यादा बड़ा है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए शिवराज को जिन सवर्णों ने बनाया है, अपने नोट वोट देकर जाए भाड़ में।

काम लो.स्वा.यां. का किया वि.या. लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टों ने

सांसद निधि में भ्रष्टाचार किया सांसद, जिलाधीश और का.यं. ने

इंदौर की लोकसभा सांसद सुमित्रा ताई जो 1987 से इस संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिये हर वर्ष रु. दो करोड़ मिलते हैं, इसका कैसे उपयोग किया गया इसका छोटा सा उदाहरण हैं, इन्होंने इस सांसद निधि का अधिकांश पैसा सन् 2001 से 2007 तक सबसे ज्यादा नलकूप खनन में किया गया, जबकि 25 वर्षों से सांसद चुनी जाने वाली ताई को भी ये मालूम था और जिन जिलाधीशों जिसमें महाभ्रष्ट मनोज श्रीवास्तव, सुलेमान खान, विवेक अग्रवाल थे, ने जो कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के यांत्रिकीय संभाग और उपसंभाग को करना चाहिये था जिनके पास नलकूप खनन की उन्नत तकनीकी की ड्रिलिंग मशीनें होती हैं। यह बात हर जिलाधीश अच्छी तरह जानता था तो भी यह कार्य जाने-माने महाभ्रष्ट लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकीय खंड के अशोक बंसल से करवाया गया, जो पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से यहां कुंडली मारे बैठा है को दिया गया, जिनका कार्य शासकीय भवनों और वाहनों की विद्युत यांत्रिकीय सेवा करना है जिनका दूर-दूर तक नलकूप खनन, पाइप डालने और मोटर लगाने से कोई वास्ता नहीं होता, न ही इसके पास कोई नलकूप खनन की मशीनें भी नहीं होती से करवाया गया, ताकि आसानी से धन हजम किया जा सके और तीनों ने मिलकर करीब 70% धन हजम भी किया गया, इसकी जानकारी को सूचना के अधिकार में प्राप्त करने के प्रयास लगातार 2005 से ही किये जा रहे थे परन्तु यहां बैठा कार्यपालन अभियंता बंसल अपनी धूर्तता और भ्रष्टाचार के चलते जानकारी देने के नाम पर हरामखोर जालसाजी पूर्ण तरीकों से भारी भरकम झूठे ही शुल्क वसूली का पत्र थमा दिया करता था और जब इसकी अपील की जाती थी तो अपने अपीलेट अधिकारी अधीक्षण यंत्री से भी जो इसके विभाग का ही होता था, अपने संबंधों के चलते मामले को उलझाकर बच निकलता था, पर इस बार इस बंदे ने जानकारी इसलिये दे दी कि दिस.12 में इसकी सेवानिवृत्ति है, लगा कि अब कोई क्या बिगाड़ लेगा, पैसा जमा करने के बाद बिना रसीद दिये/काटे ही जानकारी भिजवा दी गई, यह जानकारी बताती है कि कैसे जिलाधीशों ने सांसद निधि की बंदरबांट कर हर वर्ष में 400 से ज्यादा नलकूप खनन करवा कर राशि हड़पी गई, इसकी जांच सीबीआई, चूंकि सांसद निधि केन्द्र का धन है, और लोकायुक्त से क्योंकि कार्यादेश जिलाधीशों ने राज्य के लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकीय को दिये हैं कि 400 से ज्यादा हर वर्ष खोदे गये नलकूपों में 70% केवल कागजों पर ही पूरा कर दिया गया है। संक्षिप्त विवरण सन् 2001 में जिलाधीश मनोज श्रीवास्तव ने 24 आदेशों से 440 नलकूप खनन वि.यां.लो. निधि इंदौर से करवाये कुल धन रु. 1 करोड़ 91 लाख एक हजार 670 रु. खर्च, वर्ष 2002-03 में 1 अप्रैल 02 से 31 मार्च 2003 तक में 31 आदेशों से 349 नलकूप खनन एवं पंप स्थापना में कुल रु. 2 करोड़ 5 लाख 38 हजार का खर्च, सन् 2003-04 में 329 नलकूप खनन में रु. 2 करोड़ 3 लाख 50 हजार रु. खर्च किये गये। सन् 2004-05 में भी 248 नलकूप खनन और मोटर पंप की स्थापना में रु. 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किये गये, इसमें भी जिलाधीश सुलेमान ने 31 आदेश जारी किये, औसतन प्रति नलकूप रु. 77000 से रु. 94000 प्रति नलकूप रहीं, सन् 2004-05 में 160 नलकूप खनन और मोटर लगाई गई, औसतन कीमत और खर्च रु. 94000/- खर्च रु. 2 करोड़ के लगभग, वही हाल 2006-07 में 201 नलकूप खनन किये, लागत वहीं रु. 2 करोड़ के लगभग। परन्तु 2005-06 में जादूगरी जो की गई इसके अधिकांश नलकूप खनन के कार्यों को जून, जुलाई, अगस्त, सित. के महीनों में दिये गये, जो कि वर्षाकाल होता है, ताकि थोड़े 100-200 फुट छेद करने में ही पानी निकल आये और सारा पैसा आसानी से हजम कर लिया जाये। 600 से 1000 ड्रिलिंग का, दूसरी और अधिकांश कार्य कागजों पर ही कर लिया गया, जहां बोर करना दिखाया जाये और वहां कुछ भी न मिले तो भी साढ़े 10 इंच का मात्र एक पाइप जमीन में उतारकर कहा जा सके कि ब्लैक काटन का स्ट्रेस होने से धंसक गया, इस प्रकार से सन् 2001 सांसद निधि में का.यं. अशोक बंसल ने जो कार्य किये वो अधिकांश फर्जी थे, अधिकांश आदेश मई, जून, जुलाई और अगस्त में ही निकाले गये। 5-6 वर्षों में जो कि वर्षाकाल होता है, उस काल में लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग भी ड्रिलिंग कार्य नहीं करता है, इसलिए 6 वर्षों तक सांसद निधि में खुला भ्रष्टाचार करने के लिये लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकीय विभाग को सौंपा गया, आखिर बंसल जैसे हरामखोर ने इंदौर में 20 से ज्यादा वर्ष ऐसे ही पूरे नहीं किये।

भारत में फुटकर व्यवसाय में निवेश की वकालत

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वाभाविक है अपने राष्ट्रपति पद का उपयोग करते हुये अपनी एजेंट सोनिया और उसके पिट्ठू मनमोहन पर दबाव बनाकर भारत में फुटकर व्यवसाय के लिये स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यदि ओबामा चुनाव हार गया तो उन बहुराष्ट्रीय कं. का दिया हुआ चंदा बेकार हो जायेगा, इसलिये इन तीन महीनों में उन बहुराष्ट्रीय कं. को भारत में सीधे फुटकर व्यवसाय में निवेश के और व्यापार हेतु हर हाल में मैदान साफ चाहिये, जबकि इसके विपरीत राष्ट्र की जनता भले ही इस बात पर ध्यान न भी दे रही हो परन्तु राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को ये अहसास होने लगा है, कि विदेशी फुटकर व्यवसाय में निवेश से पूरे बाजार पर ये बहुराष्ट्रीय कं. पहले सस्ते का लालच देकर देशी बाजार में बैठे उनके छोटे स्तर के एकल, साझेदारी, निजी व कं. के व्यवसायियों को चौपट और बेरोजगार कर पहले प्रतिस्पर्धीयों को बाजार से बाहर कर फिर लूट, वसूली, मिलावट, स्तरहीन माल का तांडव मचायेंगी, जैसा कि न केवल अमेरिका, यूरोप वरन अधिकांश महाद्वीपों के राष्ट्रों में किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका राष्ट्र क्यों मंदी और विदेशी कर्ज से नहीं उबर पा रहा है, इसके विपरीत वह उन्हीं कंपनियों की व्यवसायिक गतिविधियों के लिये अपनी राष्ट्रपति पद की गरिमा को बलाये ताक रख उनका वाणिज्यिक दूत बनकर भारत सरकार पर ऐसे दबाव बना रहा है जैसे कि भारत उसका गुलाम हो और उसके बाप की जागीर हो।

भले ही अन्ना और रामदेव वर्तमान में उसके विरुद्ध आंदोलन न भी कर रहे हो, पर विदेशी निवेश के विरुद्ध कोई नया अन्ना खड़ा करना होगा, जो विदेशियों को गांधी की तरह खदेड़ेगा, वैसे पूर्व में सत्ता में रहकर कांग्रेस ने भी यही किया, वैसे पूर्व में सत्ता में रहकर कांग्रेस ने भी यही किया है। परन्तु कांग्रेस इतनी डरपोक नहीं थी कि वो हर सत्र में इस प्रकार के षड्यंत्र और रणनीति अपनायें, वो भ्रष्टाचार करते थे, तो विधानसभा में उनके जवाब देने और विपक्ष का सामना करने की भी हिम्मत रखते थे, बेशक कांग्रेसी और खासकर दिग्गी भारी भ्रष्टाचारी था, ये उसके 50% भी नहीं है पर डरने और मैदान छोड़ने में उसके 100% है। इससे न केवल पूरी भाजपा की छवि बिगड़ रही है। वरन जनता भी जनता भी स्पष्टीकरण न दे सकने और मैदान छोड़कर भागने से इन्हें रिश्ते में उनका पिता मान लेती है। अगले चुनाव तक जो 3-4 सत्र है, बेहतर होगा कि पूरे चलायें।

देशी किसानों को बर्बाद कर कृषि भूमि हथियाने का षड्यंत्र

(शेष पृष्ठ 7 पर)

तीसरी तरफ राष्ट्र की कृषि नीति में बदलाव करके विदेशी बीजों बी.टी. जीएम हायब्रिड के नाम पर विदेशी कं. से मोटा धन डकारते रहे और भारत की कृषि के अनाज, दलहन, तिलहन, नगद फसलों में कपास, मसालों में धनिया, मिर्ची, हल्दी, सब्जियों में आलू से लेकर टमाटर, लोकी, भिंडी, गिलकी, तुरई, टिंडा, करेले, बैंगन, पालक, गाजर, मूली आदि सभी फसलों के मूल बीज विदेशियों को सौंपकर उनके पेटेंट अधिकार सौंप दिये और सबके बीजों की मूल प्रजाति को राष्ट्र से ही समाप्त करवा दिया गया, पहले देश में जैविक उत्पादों से जो कृषि की जाती थी उसे नष्ट करवाकर पूरी तरह से रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कर दी गई, जिससे कृषि लागत बढ़ती गई, फिर भी किसान अपना निर्वहन करता रहा, जबकि इन बीटी, जीएम, हायब्रिड बीजों का, रासायनिक खादों को उपयोग के आदि बनाने का उद्देश्य था बेहताशा कृषि लागत बढ़ा कर किसान की कमर तोड़कर उसे जमीन छोड़ने पर मजबूर करना, जब ऐसा नहीं हो सका तो पुनः अध्ययन करवाया गया। 1985-95 तक के विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. के भारतीय कृषि के सर्वे से निष्कर्ष निकले कि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खेती में जो कृषि मजदूर काम करते हैं, वो अगर काम करना बंद कर दें, तो भारतीय किसानों की कमर टूट जायेगी और छोटी जोत वाला किसान महंगे ट्रेक्टर्स व मशीनें खरीद नहीं सकेगा, इसलिये वह खेती को बेचने/ खेत छोड़ देगा, इसलिये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश में 2004 में कांग्रेस की सरकार के बैठते ही देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की जिसका पूरा धन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों को कृषि से दूर करने के लिये 2005 में ही शुरू कर दी थी। जिसका सारा धन विदेशों से आया पर वह सारा धन जो विदेशों से आया उसे विदेशों में ही जमा करवा दिया गया और देश के राष्ट्रीय बजट में ग्रामीण विकास के मद में से इसकी व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वरूप सन् 2008 के बाद से गांवों में कृषि मजदूरों को पंचायतों ने जॉबकार्ड बनाकर पहले रु. 70, फिर 80/- और अब रु. 100/- से ज्यादा देकर गांवों के कृषि श्रमिकों को खेतों से दूर कर दिया, मजबूरी में लघु और सीमांत किसान भी खेतिहर मजदूरों रु. 125 से 150 रु. भुगतान करना पड़ता है। इससे कृषि लागत बढ़ गई और खेतिहर मजदूर को जॉब गारंटी के नाम पर उसे 40-50% को घर बैठे पैसे का भुगतान किया जा रहा है। इसलिये भी खेतिहर मजदूर खेतों में काम करना पसंद नहीं करता, इसका फायदा सीधा बहुराष्ट्रीय कं. कर रही है। अकेले आईटीसी ने 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हथिया ली, फिर रिलायंस, सहारा भी लाखों एकड़ जमीन की हेरा-फेरी में व्यस्त हैं। जिन्हें बाद में बहुराष्ट्रीय कं. हथिया लेंगी और इस लाइन में पेप्सी, हिन्दुस्तान लीवर जो युनिलीवर इंग्लैंड की भारतीय सहायक कं. हैं।

भारत पर बहुराष्ट्रीय कं. की निगाहें इसलिए गढ़ी हुई है कि यहां कि न केवल जमीन उपजाऊ है वरन यहां का मौसम भी निश्चितापूर्ण है, पहले कृषि पर कब्जा होगा, फिर बाजार पर, फिर सरकारों पर और उसके बाद हम सब न हिन्दू रहेंगे, न मुसलमान रहेंगे, गुलाम की औलाद हैं गुलाम रहेंगे, माता, डिप्शीरिया, पोलियो जैसे अनेकों टीकों से बच्चों को नपुंसक बनाने का षड्यंत्र 30 वर्षों से ज्यादा समय से चल रहा है, भारतीय पुरुष नपुंसक होगा, तो भारतीय महिलाओं से फिर ये विदेशी बच्चे पैदा करेंगे। जैसा कि पूर्व में अंग्रेजों ने किया था, एक तरफ इस खेल में लाखों करोड़ सोनिया, मनमोहन और ग्रामीण मंत्री डकार कर विदेशों में जमा करवा रहे हैं तो दूसरी ओर वह पैसा जिला पंचायत कार्यालय से लेकर पंचायतों तक हजम किया जाकर सबको भ्रष्ट बनाया जा रहा है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कं. को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है और वे आसानी से लाखों एकड़ जमीन कब्जे में कर रही हैं हर साल। 125 करोड़ जनता को ऐसे उलझाया गया है।

जल निगम बनाकर अब लूटेंगे जल के नाम

पृष्ठ 8 का शेष

इसके बाद भी हर वर्ष विद्युत की कीमतों में न केवल बढ़ोत्री की जा रही है वरन अंधेरा भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। गांवों में 18-18 घंटे विद्युत नहीं रहता और जब श्योपुर जिले के किसानों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई। इन सबके साथ ही बिजली के 50 से 200% तक तेज इलेक्ट्रानिक मीटर लगाकर भी अनाप-शनाप वसूली की जाती है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के बिल भी हजारों में भेजे जाते हैं। जबकि न तो उनकी कुल आय उन बिलों के बराबर होती है, नहीं उनके घरों में बल्ब और पंखा चलने के अतिरिक्त कुछ चलता है। कुल भार 500वाट का और बिल हजारों में, बिल भरने के चक्कर में उन गरीबों की दो वक्त की रोटी भी छीन लेते हैं। जो गरीब किसान उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पाते हैं। उनकी गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलवाने में भी नहीं चूकते ये कं. वाले, ये हाल किया है शासकीय विद्युत मंडल का इन हरामखोर सत्ताधीश धूर्तों ने।

जो हाल इन धूर्त सत्ताधीश मुख्यमत्री, मंत्रियों और शासकीय अधिकारियों ने म.प्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करवाकर सब कुछ निजी हाथों में सौंपकर अब मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेताओं और अधिकारियों की बसों ने लूट मचा रखी है। वही हाल म.प्र. विद्युत मंडल को भंग करके बनाई गई कंपनियां कर रही हैं। वही हाल जल निगम करेगा, पहले जल निगम गांवों में चलेगा, फिर जनपदों में, फिर छोटे शहरों में, फिर बड़े शहरों में जल व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर पानी बेचा जायेगा, जनता के जीवन यापन के लिये नहीं वरन अपना लाभ कमाने के लिये, जो अरबों रु. की जनता को धन से टंकियां, पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। वे सब धीरे जालसाजी और षड्यंत्रों से मोटा धन डकार कर कंपनी भारत के प्राकृतिक जलस्त्रोतों पर कब्जा कर जनता को बूंद-बूंद पानी के लिये तरसा देंगी।

मैक्सिकों में भी विश्व के बड़े पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही विश्व बैंक ने पहले विकास के बहाने ऋण पिलाया, फिर कर्ज न चुकने की दशा में अपनी कंपनियां खोली। उन्होंने 10-15 वर्ष में वही का पानी इतना महंगा कर दिया कि जनता पानी को तरसने लगी। अंत में जनता के कंपनियों के आफिस में आग लगाकर खदेड़ दिया, यही हाल हमारे यहां अभी दूसरी अवस्था में कदम रख रहा हैं, फिर ये सरकारी कंपनियां पूंजीपति हथिया लेंगे, बाद में अभी जो पानी रेल्वे प्लेटफार्म से लेकर रेल्वे कोच में 15 रु. ली. बिक रहा हैं, क्योंकि हरामखोर रेल्वे उसके अधिकारी जनाबूझकर रेल्वे प्लेटफार्मों पर और कोच में अच्छा साफ पानी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसलिये वही पानी कंपनियां रु. 1/- ली का साधारण मिनरल वाटर के नाम पर 15 का बेचती है। फिर वही पानी घरेलू उपयोग के लिये रु. 15/- लीटर में कंपनियां, नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों से छीनकर उन्हें मोटा कमीशन बांटकर उन्हें खरीदकर आपूर्ति करेंगी, अमीर और मध्यमवर्गीय तो खरीद लेगा, पर मरण निम्न मध्यम वर्गीय, गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे वालों का ही होगा, फिर जो भी नेता चुनकर आता है उसको मालूम है कि उसकी औकात मात्र 5 वर्ष हैं, जितना, जहां से, जैसे लूट और वसूल सकता है वसूलता है।

लोकतंत्र भारत का लूटतंत्र बन चुका है, हर हरामखोर सत्ताधीश चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, तृणमूल, एडीएम के हो, सब डकैत बन जाते हैं। जनता को कैसे लूटना है, इसकी गिद्ध ताक में रहते हैं। वही म.प्र.में भाजपा कर रही हैं, जिस पूंजीवाद के विरुद्ध वह धरने प्रदर्शन करती थी अब वह उसके चरणों में लौट लगा रही हैं, तो मात्र मोटा धन अंटी करने के लिये।

साप्ताहिक समय माया

पेक्ड खाद्य, टीकाकरण, ड्रग टायल, साफ्ट ड्रिंक सबका उद्देश्य युवा पीढ़ी की बर्बादी

सरकार और बहुराष्ट्रीय कं. का षड्यंत्र- युवा हों नपुंसक

ताकि गुलाम, सरकार और बहुराष्ट्रीय कं. के षड्यंत्रों के विरुद्ध आवाज भी न उठा सकें

भारत भूमि देवों की भूमि रही है, तो दानवों ने अपनी तांडव लीला इसी धरती पर की हैं, जब-जब मानव, मानव से महामानव बन जनता का घोर शोषण कर दानव बना, उनसे शोषण, आतंक से जनता को मुक्त करने महापुरुषों ने जन्म लेकर आतंक से जनता को मुक्त करवाकर जन सामान्य को कष्टों से मुक्त करवाया, ऐसा हमने धर्मग्रंथों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जो निष्कर्ष हमने निकाला, वह निष्कर्ष हमसे पूर्व महाधूर्तों, संकर प्रजाति के अमेरिकी कं. और ब्रितानी हमारी समझ से पूर्व ही निकाल चुके थे, उन्होंने उसका सदुपयोग बड़ी षड्यंत्रकारी तरीके से भारत की स्वर्ण उर्वरा भूमि को हथियाने के लिये 50-60 वर्ष पूर्व से ही करना शुरू कर दिया था।

भारत की स्वर्ण उर्वरा भूमि पर कब्जे और यहां की जनता को गुलाम बनाने के लिये जरूरी था कि सबसे पहले यहां के युवाओं को नामर्द, नपुंसक, बैलों की भांति बना दिये जाये ताकि नापुंसकों को आसानी से अपनी तरह से हांका जा सके, बस उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सस्ता अनाज उपलब्ध करवा दिया जाये, वो दो वक्त का भोजन कर जुगाली करता हुआ, अपने आकाओं, सरकार के इच्छानुसार वोट ठाले, खेतों, फैक्ट्रियों, खदानों, जंगलों में काम करता रहे, इसलिये कांग्रेस के गिद्ध 67 % आबादी को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिये राज्यसभा और लोकसभा में बिल लायेगी, नर प्राणी को प्रकृति उसके वीर्य की बूंदों से पृथ्वी पर जीवन के चलन को बनाये रखने के लिये जन्म देती हैं, मानव में यही वीर्य उसके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति और ओज तेज को संचालित करता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित हैं, यही वीर्य जहां स्त्रियों की योनि में पहुंचकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है, वही स्त्री का संसर्ग पुरुष का पूर्णता प्रदान कर उसके जीवन जीने के औचित्य को सिद्ध करता है। पुरुष के वीर्यहीन होने पर वह तेजहीन, शक्तिहीन होकर बैल की भांति जीवन व्यतीत करने के लिये विवश हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता हैं, न उसे क्रोध आता है न आक्रोश व्यक्त करता है, कांग्रेसी धूर्त सत्ताधीशों को ऐसे ही क्लांत, वोट देने वाले बैलों रूपी कार्यकर्त्ताओं से लेकर जनता की आवश्यकता और अपेक्षा रही है, ये वहीं कांग्रेस हैं, जो एक तरफ बच्चों के बाल्यकाल से लेकर महाविद्यालयीन युवाओं से 65 वर्ष के आजाद भारत में भी जन,गण,मन, अधिनायक की जय करवा-करवा कर गुलामी का आह्वान करते हुए आकाओं की जयकारें करवा रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी और यूरोपीय दवा बनाने वाली बहु विधि, विविध व्यवसाय करने वाली बहुराष्ट्रीय कं. की विश्व स्वास्थ्य बर्बादी संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार के नाम पर भारतीय बच्चों में विभिन्न टीकों के नाम पर शरीर को कमजोर करने के लिये 50 वर्षों से ज्यादा समय से टीकाकरण करवा रही हैं, ताकि इस राष्ट्र की पूरी पीढ़ीयां नपुंसक बन जाये और उनकी औलादें कमजोर और नकारा ही पैदा हो, जब यह टीकाकरण कार्यक्रम भी इस षड्यंत्र को सफल नहीं बना पाया तो फिर मीठे साफ्टड्रिंक्स जो कोका-कोला, थम्सअप, पेप्सी, माजा, ताजा जैसे सैकड़ों पेय पदार्थों में रसायनों के साथ खेती के कीटनाशकों का अत्यंत घातक विष अल्प मात्रा में मिलाकर इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी को परोसा जा रहा हैं, जो लोकसभा की कैंटीन में पूर्णतः प्रतिबंधित है, आखिर क्यों इस राष्ट्र के युवाओं को शीघ्र मौत और जनता के चुने लोकसभा के बूढ़ों को जिंदगी दी जा रही हैं, इसलिये ही न ताकि इन बुढ़ों की औलादें इस देश को गुलामों का हांकी रहें पीढ़ियों तक, ये शीतल पेय युवाओं को बीमार, नामर्द बना रहे हैं। दूसरी तरफ इसी संसद के धूर्तों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 2006 इसलिये बनाया गया ताकि ये धूर्त बहुराष्ट्रीय कं. खाद्य पदार्थों में इतने विषैले रसायन मिला दें ताकि उसको खाने वाली पीढ़ी शीघ्र ही बीमार, मोटी, नपुंसक और नामर्द हो जाये और जो सीधे ही छोटे-छोटे व्यापारी अभी जो व्यवसाय कर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं उनको कानून का भय दिखाकर लाखों में अर्थदंड कर अपना व्यवसाय समेट लें, जिससे इन बहुराष्ट्रीय कं. वालमार्ट, मेक्डोल्ड, हिन्दुस्तान लीवर, आईटीसी, पेप्सीको, पारले, रिलायंस, टाटा, सहारा अपना व्यवसाय करें, उनके खेतों में रसायनों और मशीनों से खेती करके जो पैदा करें उसे वो अपनी मनमाने तरीके से पैक करके अपने मनमाने दामों पर बेच सकें, जिसके सीधे परिणाम वर्तमान में बाजार में मिलने वाली चाकलेट, बिस्कुट, आईसक्रीम जिसमें विज्ञापनों में दूध दिखाया जाता हैं, जब जानवर गाय, भैंस ही नहीं है, तो दूध कहां से आ रहा है, स्वाभाविक है केवल झूठे विज्ञापनों से युवाओं को लुभाकर घातक रसायन चाकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीमों में खिलाकर पुरुषों को नामर्दी तो युवा स्त्रियों को 40-45, 50 वर्ष में होने वाली योनि रोगों, डिंब नलिका में सूजन, गर्भाशय के रोग बांटे जा रहे हैं। जिसे डाक्टर्स भी स्वीकारते हैं कि ये घातक रोग, घातक रसायनों के भोजन में सेवन से उत्पन्न हो रहे हैं। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि फास्ट बड़ी दिल की बीमारियों, किडनी लीवर बांटकर युवाओं को मरीज बूढ़ा और महंगी घातक जिसमें बीपी उच्च और निम्न, मधुमेह, आर्थराइटिस आदि की दवाओं का गुलाम बनाकर जिंदगी जीने के लिये मजबूर कर रहे हैं। ताकि विदेशी कं. की ऊंची और महंगी दवाओं का न केवल वर्तमान पीढ़ी में वरन भावी पीढ़ी में भी बाजार बना रहे। भारत में विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ा संगठन ने युरोपीय कं. की नई दवाओं के प्रयोग के लिये सन् 2005 तत्कालीन भारत के स्वास्थ मंत्री अंबुमणि रामदास को मोटा अरबों डालर में धन देकर बिना अनुमति, बिना किसी बंदिशों के बिना केन्द्र व राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अनुमति और बिना जानकारी दिये ही देश के किसी भी चिकित्सालय में कभी भी, किसी पर भी, किसी भी रोग में, बिना उसकी जांच चूहों, गिनी पिग्स, खरगोशों, बंदरों और चिंपाजी आदि पर की जांच किये सीधे ही भारत में किसी भी बीमार पर औषधि परीक्षण की छूट दे दी, वर्तमान हालात ये हैं कि भारत के गिद्ध और लालची डॉक्टर न केवल सरकारी वरन निजी चिकित्सालयों में भारत के 125 करोड़ मानव रूपी जानवरों पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप देशभर में 10 से 20 लाख लोग या यों कहें कि निजी व शासकीय चिकित्सालयों से निकलने वाले 50% शवों में औषधि परीक्षण मौत का कारण रहा और जो जीवित बच जाते हैं।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मंगल के सहारे चुनावी दंगल जीतने का शिगूफा

मंगल पर यान या चुनावी अभियान

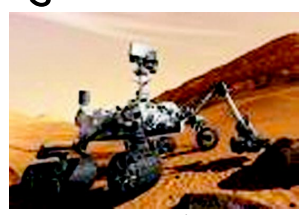

अमेरिका ने घोषणा की कि 6 अगस्त को उसका क्युरोसिटी नामक यान मंगल की सतह पर उतर कर खोज कर रहा है। जो चंद्रमा पर उतरने की तरह की पूरी बकवास हैं। वहां से जो सतह के फोटो भेजे है, एक में किसी रेगिस्तान के फोटो लगा दिये हैं, दूसरे में भारत की किसी ऐसी सड़क के फोटो लगा दिये जिसमें ठेकेदार और इंजीनियर के भारी भ्रष्टाचार के चलते जो सड़क बनाई गई थी जो पहली बरसात में

ओबामा राष्ट्रपति के रुप में फेल, मंगल कितना मंगल करेगा

ही उसकी गिट्टी चूरी बिखर गई, दोनों ही फोटो एक-दूसरे के विरोधाभासी है। पत्थर-गिट्टी, कंकड और दूसरे में रेगिस्तानी टीले जिसकी वास्तविकता एक साधारण आदमी भी समझ सकता है।

दूसरी ओर 5.7 करोड़ कि.मी. का अनुमानित सफर किस ईंधन से बिना माध्यम के, जैसे कि पेट्रोल को जलाने के लिये आक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कैसे पूरा किया गया। जबकि 5.7 करोड़ कि.मी. में 5.699 करोड़ कि.मी. सब कुछ शून्य अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के शून्य में न कोई ईंधन कार्य करेगा और सारी गति भी शून्य हो जाती है। फिर राकेट भी धरती के हवा के वायुमंडल में ईंधन को जलाकर ही आगे बढ़ता है और वायुमंडल से बाहर निकलने के बाद उपग्रहों को छोड़ देता है। जो 2-3 हजार कि.मी. की ही दूरी होती है।

हवाई जहाज के टर्बोजेट भी हवा को खींचकर पीछे फेंकते हैं और हवाई जहाज डैनों के सहारे हवा पर तैरता हुआ आगे बढ़ता है। चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में वायु का माध्यम है पर अंतरिक्ष में सबकुछ शून्य है वह भी अरबों कि.मी. का, फिर जैसे सूर्य के निकट जायेंगे, धरती की साधारण धातुओं और यान पर सूर्य की 500 सेंटीग्रेड से लेकर 2000 सेंटीग्रेड तक का तापमान मानव निर्मित यानों को झेलना पड़ेगा, जिससे सारे रेडियो, कैमरे, इंजिन कार्य करना बंद कर देंगे, तो किस माध्यम से रेडियो संकेत, तरंगे इन तक पहुंची।

पूरे विश्व में केवल अमेरिका ही अपनी दादागिरी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठता और उच्चता बनाये रखने के लिये हर तरह के शिगूफे छोड़ा करता है। जैसे उड़नतश्तरीयां, जबकि वो सारे अमेरिकी जासूसी यान थे, जिसकी पोल उसके ही सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने खोल दी थी, ये चंद्रमा पर भी कभी नहीं पहुंचे, पर 1969 के आर्मस्ट्रांग के उतरने के सहारे लंदन, अमेरिका में जरूर जनता को बेवकूफ बनाकर अरबों रु. के प्लाट जरूर बेच दिये गये। कहानी यहां तक ही समाप्त नहीं हुइर्त्त। चंद्रमा और मंगल पर पानी के शिगूफे भी बहुत छोड़े गये, भारत सरकार में बैठे लोगों ने चंद्रमा से पानी लाने के राग भी अलापे, जबकि तीन चौथाई हिस्से के पानी का उपयोग कर नहीं पा रहें। समय माया ने तब भी इनके चंद्रमा और मंगल पर पानी के शिगूफे को तार-तार बिखेर दिया था, समय माया ने मार्च 2009 के अंक में प्रकाशित किया था, जिस पिंड/ग्रह पर बादल, उस पिंड/ग्रह पर पानी। जिस ग्रह या पिंड पर बादल नहीं, वहां न पानी न जिंदगानी और ग्रहों पर बादल धरती से भी दूरबीन के जरिये देखे जा सकते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं, जब चंद्रमा और मंगल पर बादल नहीं तो कोई पानी या तरल पदार्थ नहीं। इसलिए जीवन भी संभव नहीं। यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर पूरी दुनिया को ईमेल से प्रकाशित कर भेजा गया तब जाकर चुप हुये।

फिर मंगल पृथ्वी का उपग्रह नहीं वह सौर मंडल का ग्रह है। स्वाभाविक है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जो 5.70 करोड़ कि.मी. का फासला पूरा करने में सीधा प्रभावित करेंगी। अमेरिका का इतिहास रहा है, जालसाजी पूर्ण तरीके से अपनी वाहवाही लूटने, सर्वोच्चता, सर्वश्रेष्ठता दिखाने का, जैसे कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाने का, जबकि उसके हमशक्ल को पकड़ कर लटकाया गया जबकि असली सद्दाम जार्डन में परिवार के साथ रह रहा है। इसी प्रकार ओसामा को गोली मारने का, जबकि असली ओसामा सित. 2006 में लीवर कैंसर से ही मर चुका था, ये सब चुनावी हथकंडे अमेरिकी राष्ट्रपति जनता को बेवकूफ बनाने के लिये करते आ रहे हैं। जिसकी सत्यता को समय माया अपने प्रकाशनों में करता रहा है।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा हर जगह हर कदम अमेरिकी प्रशासन को संभालने में असमर्थ रहा है। यहां तक कि हाल ही में अमेरिकी गुरुद्वारे में हुई आतंकवादी घटना न केवल यह सिद्ध करती है वरन यह भी जगजाहिर हो चुका है, कि अमेरिका में भी चारों तरफ रंगभेद, जाति और नस्लभेद का बोलबाला है, यह भी चुनावी स्टंट का हिस्सा हो सकता है। ओबामा, अमेरिका वासियों के लिये तो कुछ अच्छा नहीं कर पाये, अमेरिकी अर्थव्यवस्था न केवल पटरी से उतर चुकी है वरन भारी कर्ज में भी डूबी पड़ी है, बेरोजगारी चरम पर है। तो वोट कैसे मांगेंगे तो मंगल पर यान के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार करने के लिये अमेरिकी जनता को भ्रमित किया जा सके और पुनः हथियाई जा सकें। वैसे 130 अरब डालर का खर्च बताया गया, उससे काफी अमेरिकी कर्ज कम किया जा सकता था, या उस धन से 1.3 लाख अमेरिकी युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था, वह ज्यादा जरूरी था, चुनाव जीतने के लिये भी, इस शिगूफे पर भारत सरकार भी रु. 450 करोड़ खर्च करने जा रही है।

पूंजीवाद की ओर बढ़ते कदम, सपनि, विद्युत, सड़कों के बाद अब जल निगम

जल निगम बनाकर अब लूटेंगे जल के नाम

प्राकृतिक जल स्त्रोतों को कं. को सौंपकर कमीशन डकार करेंगे वसूली

म.प्र. में सत्ता में कोई भी बैठे चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सत्ता में आते ही सात पीढ़ियों के लिये धन इकट्ठा करने की चाहत जागृत हो उठती हैं, तत्काल में जनता के सुख-दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, कोई भरोसा नहीं, कल जनता चुने न चुने, जरूरी है कि अभी वसूली कर लो, जो भी खरीददार मिले, गिरवी रखने वाला मिले, बेचो और गिरवी करो अपना माल अंटी करो, कल किसने देखा है। सत्ताधीश किसी भी पार्टी के हों, जो लूट सके तो लूट, अंत काल पछतायेगा, प्राण जायेंगे छूट' ही सबका उद्देश्य है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। इसके साथ ही भारत में बहुत से धर्म है और हर धर्म कहता है, नंगा मुट्ठी बांधे आया था, खाली हाथ पसारे जायेगा। इसके विपरीत बेशर्म सत्ताधीश शूकरों को भी सब ज्ञात है, परनतु सब मिलकर राष्ट्र को बहुराष्ट्रीय कं. को गिरवी करने पर तुले हैं। सबकी आंखों पर मुद्रा का चश्मा चढ़ा है। इन्हीं बहुराष्ट्रीय कं. ने मेक्सिको में जब पानी पर कब्जा कर, प्राकृतिक स्त्रोतों पर प्राप्त देश के पानी को ही महंगा और दुर्लभ बना दिया, तो अंत में मेक्सिकों की जनता ने मिलकर इन सारी कंपनियों को खदेड़ कर मार-पीट कर भगाया। शायद भारत के सत्ताधीश गिद्धों को तो वर्तमान में हर प्राकृतिक संपदाओं को बेच और गिरवी कर अंटी करने की पड़ी है। इन हरामखोरों का तो वश नहीं चलता वरना ये सूर्य के प्रकाश और प्राकृतिक हवा पर भी बहुराष्ट्रीय कं. को ठेका देकर वसूली कर लें, पर पानी पर वश चला तो पानी बेचने के लिये अवश्य ही इन जालसाजों ने जल निगम बना दिया जो कि अब प्राकृतिक और मानव निर्मित स्त्रोतों से जल एकत्रित कर उसे भी अपनी मनमानी कीमतों में बेचा जायेगा। जबकि वर्तमान तक जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से लेकर नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों यहां तक की पंचायतों के अंतर्गत निर्मित जल स्त्रोतों को जनता के धन से विकसित किया गया है। जनता की जमीन पर विकसित किया गया है, फिर इसकी लागत और वर्तमान कौन, किसको चुकायेगा? यदि चुकायेगा तो उस धन का कहां, क्या होगा? ये सबसे गंभीर मुद्दा है, इसकी चर्चा कौन करेगा? सत्ता, सत्ताधीशों के बाप की जागीर नहीं, जो जब मन में आये किसी को भी बेंच दें, गिरवी कर दें। जैसा कि म.प्र. विद्युत मंडल की कं. को बनाकर किया जा रहा है। एक तरफ विश्व बैंक का ऋण हजम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ केन्द्र व राज्य शासन से विद्युत के लिये मिले पैसे को हजम कर रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803